MOTION FOR EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF THE REPORT OF THE JOINT COMMITTEE OF HOUSES ON THE CENTRAL AND OTHER SOCIETIES (REGULATION) BILL, 1974

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति, जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"केन्द्रीय तथा अन्य समितियां (विनियमन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थित करने के लिए नियत समय को राज्य सभा के सत्तानवेवें सत्र के अन्तिम दिवस तक और बढ़ा दिया जाए ।"

The question was put and the motion was adopted.

LEAVE OF ABSENCE TO SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI

MR. CHAIRMAN : I have to inform Members that a letter dated 11th May, 1976, has been received from Shri Sundar Singh Bhandari to the effect that leave of absence from attending the 96th Session of the House may be granted to him on account of his detention.

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Shri Sundar Singh Bhandari for remaining absent from all meetings of the House during the 96th Session of the Rajya Sabha?

(No, Hon. Member dissented.)

MR. CHAIRMAN : Permission to remain absent is granted.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूं । कल आप नहीं थे जब मैंने यह बात उठाई थी कि जो सदस्य शपथ नहीं ले सके क्योंकि जेल में हैं, यदि आप उचित समझें, उपसभापति, या जिनको भी उपसभाध्यक्ष की तालिका में आपने रखा है वह पांच मिनट के लिये चला जाए ताकि सदस्य बकायदा शपथ ले लें । ऐसा न होने का परिणाम यह हो रहा है कि हमारे यहां के श्री एल० के० अडवाणी जो हैं उनके घर का टेलीफोन कट चुका है और सी० जी० एच० एस० की जो सुविधाएं उनको मिली हुई थी वह भी वापस ले ली गई हैं क्योंकि वह शपथ नहीं ले सके हैं । अगर इसमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं है तो मैं समझता हूं इस विषय पर अवश्य विचार करें ।

MR. CHAIRMAN : There appears to be a precedent in such a case where we have given leave to remain absent. But what you have suggested will be looked into.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Finance Bill, 1976

SECRETARY-GENERAL : Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha: "In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Finance Bill, 1976, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 17th May, 1976.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

MR. CHAIRMAN : Now, the Appropriation (No. 4) Bill 1976. Mr. Nathi Singh.

THE APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1976 .—*contd.*

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : सभापति जी, कल इस बिल का समर्थन करते हुए मैं निवेदन कर रहा था कि जहां हमारे बजट में कुछ सुख और सुविधाओं की चीजों में, चाहे रैफरीजिरेटर हो, या दूसरी सुविधाएं हों उनमें टैक्स की सीलिंग कम की गई है वहां हमें किसानों को भी सुविधाएं देनी चाहिएं । कल हमारे एक सदस्य बोल रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर आदि की सुविधाएं पूरी तरह से किसानों को नहीं मिल रही हैं । किसान की जो फसल है उस की बीमा योजना का कोई प्रबन्ध नहीं

[श्री नत्थी सिंह]

है । उसकी फसल सुरक्षित नहीं है । उसकी फसल को कभी आग से, कभी-कभी बरसात से, कभी बाढ़ से नुकसान होता रहता है । हमारा कहना है कि अगर बीमा योजना लागू कर दी जाए तो किसानों की फसल सुरक्षित रह सकती है । तभी हम कहेंगे कि हम इतना पैदा करें कि हमारे देश में सुरक्षित अन्न का भंडार हो और उसे हम बाहर भी भेज सकें ।

दूसरी एक और बात की ओर मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कृषि अनुसंधान परिषद् के ऊपर भी आप व्यय कर रहे हैं, ऐसा बजट में कहा है । बड़ी अच्छी खोज हुई है और कृषि के क्षेत्र में इससे बहुत बड़ा फायदा मिला है इसमें कोई दो राय नहीं हैं । इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि हम कितने बेखबर हैं कि हमने किसानों को कितना कमजोर और असंगठित मान लिया है कि हम उनकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते । आपने अभी शंकर बाजरा 3 और 4 निकाला और किसानों को बांटा । हुआ यह कि जिन किसानों को आपने यह बीज बांटा उनकी सारी फसल नष्ट हो गई, जहरीली हो गई । उस बीज से कुछ भी पैदा नही हुआ ।

[Mr. Deputy Chairman in th? Chair]

सरकार से जब यह कहा जाता है कि जो बीज आपने दिये हैं या आपकी एजेंसियों में दिये हैं उनसे नुकसान क्यों हुआ, कुछ भी पैदा क्यों नहीं हुआ तो उनसे कोई जवाब नही बनता । हमारा कहना है कि जिन निगमों ने या कारपोरेशन्स पर बीज दिये हैं उनसे इसकी क्षति-पूर्ति किसानों को मिलनी चाहिये । इस तरह का आपको प्रावधान रखना चाहिये । मेरा निवेदन है कि जहां हमारी प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पीड़ित, सबसे शोषित और गिरे हुए वर्ग को ऊपर उठाने की बात कही है वहां इन बातों को भी अपने कार्यक्रम में लेना चाहिये । हम शहर में रहने वालों की तरफ तो ध्यान देते हैं लेकिन किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और वे बेचारे धूप और सर्दी में मेहनत करके भी बुरी तरह से बरबाद हो जाते हैं । उनके लिये न्यूनतम सुरक्षा के प्रबंध करने में हम लापरवाही बरतें यह चीज ठीक नहीं है । हम अपने समाजवाद के ध्येय की ओर तभी निष्ठावान माने जाएंगे जब इस ओर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा ।

उपसभापति जी, कल चौधरी रणबीर सिंह जी कह रहे थे कि किसान की पैदावार का सही मूल्य उसे मिलना चाहिये । यहां पर बैठे हुए बुजुर्ग नेता कल धीरे-धीरे कह रहे थे कि अगर उनका क्षेत्र, जहां से वह चुनकर आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है तब तो वह बात करेंगे कि गेहूं के दाम अच्छे दो, दाम ऊंचे करो । अगर वह शहर से आता है तो कहेगा कि गेहूं के दाम गिराओ । हम स्वयं अपने विश्वासके प्रति सही नहीं हैं ।

मैं समझता हूं कि यह मानना ठीक नहीं है कि अगर किसानों को ज्यादा मूल्य दिये जाएंगे तो उससे उपभोक्ता को मंहगाई का शिकार होना पड़ेगा । मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को ऐसी दाम नीति तय करनी चाहिये जिसके अन्तर्गत कल कारखानों में जो चीजें बनती हैं, उनकी जो लागत आती है उसको ध्यान में रखते हुए चीजों का मूल्य तय किया जाय और उसी प्रकार से खेतों में जो चीजें पैदा होती हैं उनकी लागत को ध्यान में रखकर उनका मूल्य निश्चित किया जाये और इन दोनों के मूल्यों में आपस में कोई संबंध होना चाहिए । इस प्रकार की नीति अगर अपनाई जाएगी तो इससे उपभोक्ता को मंहगाई का शिकार होने से बचाया जा सकता है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने किसानों से 105) रु०

प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा और यह भी सही है कि जौ के मूल्य जब बाजार में 14 रु० तक नीचे आ गये थे, तो सरकार ने उसका मूल्य 65 रु० प्रति क्विंटल निश्चित किया लेकिन इस बारे में स्थिति यह है कि किसानों से जौ खरीदा नहीं जा रहा है। एक तरफ तो यह डिसीजन लिया जाता है कि किसानों को राहत दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ किसान अपने खेत में जो चीजें पैदा करता है उसको खरीदा नहीं जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसान अपने खेत में जो भी चीजें पैदा करता है उसको खरीदा जाना चाहिए। गांवों के अन्दर यह स्थिति भी देखने में आई है कि एफ० सी० आई० के लोग कई बार किसानों से किसी अनाज को नहीं खरीदते हैं और उसी अनाज को व्यापारी से खरीद लेते हैं। इस प्रकार की नीति से किसानों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि किसान है उनको खेत में जो वस्तुएं पैदा करता उनको सरकार द्वारा खरीदा जाना चाहिए।

एक अन्य बात मुझे गोदामों के संबंध कहनी है। आज सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि देश के अन्दर गोदामों की कमी है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर सहकारी संस्थाओं के काफी गोदाम हैं। सरकार इन गोदामों में अपना अनाज का भंडार जमा कर सकती है और इन गोदामों को किराये पर अपने पास रख सकती है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अगर कदम उठाये जाएंगे तो इससे किसानों को भी फायदा होगा।

इसके साथ-साथ मैं सरकार का इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्यों के अन्दर जल के वितरण की भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। राजस्थान की तरफ से बार-बार इस बात की मांग की जाती है कि गंगा और यमुना के पानी का कुछ हिस्सा उसको भी मिलना चाहिए। यमुना का जो पानी है उसका 22 परसेंट हिस्सा राजस्थान का माना गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि गंगा बेसिन में पानी है ही नहीं। एक तरफ तो यह बात कही जाती है और दूसरी तरफ बहुत-सा पानी बाढ़ में बह जाता है और समुद्र में चला जाता है। इसलिए मेरी यह राय है और जैसा कई अन्य माननीय सदस्यों ने जल को एक राष्ट्रीय सम्पत्ति माने जाने की बात कही है, उस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जल के वितरण को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले। आप जानते हैं कि राजस्थान नहर का कार्य एक काफी लम्बे अर्से से चल रहा है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को चलाया जाना ठीक नहीं है। इस योजना को एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी राजस्थान के रेगिस्तान को नख-लिस्तान के रूप में बदला जा सके।

जहां तक प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का सवाल है, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है। ग्रामीणों की ऋण मुक्ति के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कदम उठाये गये हैं और बंधुआ मजदूरी प्रथा को खत्म करने के लिए जो पग उठाये गये हैं वे सब प्रशंसनीय हैं। लेकिन इस सिल-सिले में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि ग्रामीणों की ऋण मुक्ति के लिए एक या दो वर्ष के लिए कर्जा वसूली स्थगित जरूर कर दी गई है, लेकिन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए कोई आलटरनेटिव इंतजाम नहीं किया गया है। गांवों के अन्दर ग्रामीणों को ऋण मिलने में बड़ी कठिनाई हो रही है। सहकारी संस्थाओं द्वारा या ग्रामीण बैंकों द्वारा उनको ऋण देने की बात कही गई है। रिजर्व बैंक ने सहकारी संस्थाओं को इस

[श्री नत्थी सिंह]

बात की छूट दे दी है कि वे गहने, जेवर और सोना, चांदी लेकर ग्रामीणों को ऋण दे सकते हैं। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर कितने लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास सोने-चांदी के जेवर होते हैं ? इसलिए सोचना यह है कि हमको आल्टर-नेटिव क्रेडिट की व्यवस्था कैसे करनी पड़ेगी और इसके रिजर्व बैंक को भी अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। इस बारे में जो आप कर रहे हैं, इस बारे में जो आप जूझे हुए हैं, एक कमेटी बैठाई है रिजर्व बैंक में और सहकारी बैंकों में जो दीर्घ और अल्पकालीन ऋण देते है उनको एक कर दो। आपने रिजर्व बैंक को एग्रिकलचरल क्रेडिट दे दिया, वे किसानों को ऋण देने की बात करते थे, उन्होंने दूसरा खोल दिया ए० आर० सी०। वे मल्टी परपज एजेंसी में विश्वास करते हैं। अगर आप राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों को एक ही एग्रिकलचर बैंक बना देते तो मैं समझता सही दिशा में जा रहे हैं। एक तरफ आप मल्टी परपज एजेंसी में विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ जो बैंक ठीक काम कर रहे हैं, जिन्होंने लांग टर्म में काफी ऋण दे दिया—एक अच्छी व्यवस्था—थी उनके काम में व्यवधान पड़-जाएगा। हमें सोचना यह चाहिए कि उप-भोग के लिए हम ऋण दें किसान को। मजदूर को खाने के लिए जरूरत है। उसके लिए रिजर्व बैंक की नीति बदलें। गांव के उस गरीब को जिसको 20-सूत्री कार्य-क्रम के अन्तर्गत इन्दिरा जी ने आशा दी है, विश्वास दिया है, एक तरह से संरक्षण दिया है, आज उसको कर्जा नहीं मिल रहा है। तो नीति में निश्चित रूप से प्रावधान होना चाहिए कि ग्रामीण बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक का उपयोग किया जाए जो गरीब ग्रामीण के उपयोग के लिए, रोजमर्रा की जरूरत के लिए, उसके बच्चे की शिक्षा के लिए ऋण दें। इस संबंध में मैं एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में, बल्कि सारे हिन्दुस्तान में ही लोगों को जमीनें दी गई इस बात के लिए कि वे अपने मकान बनाएं। जिनके पास जमीनें नहीं थी उनका बड़ा कल्याण हुआ है। लेकिन जो थोड़ी देर के लिए यह आशा भी जगी कि ग्रामीण भवन निर्माण सहायक समितियों से कर्जा मिलेगा, पक्के मकान बनेंगे, उसके बाद कुछ को तो वह मिला, लेकिन फिर एक दम ब्रेक लग गया। कहा गया कि एल० आई० सी० के पास पैसे नहीं हैं। तो उसके लिए प्रायरिटी देकर पैसा देना पड़ेगा। एक तरफ बड़े-बड़े भवन देश में बनते हैं और दूसरी तरफ जो एक गामीण की न्यूनतम आवश्यकता है वह नही दें, जब कि इसके लिए हमने 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जमीनें देने की व्यवस्था की है, तो मकान बनाने के लिए पैसे का प्रबंध हमें करना ही चाहिए और उनको कर्जा भी मिल जाए जो कि बहुत से केसेज में नहीं मिला है।

Time bell rings

मैं शार्ट में अपनी बातें कह रहा हूं। कल जब मेरे बोलने का टर्न आया था कल समय शार्ट नहीं था, इसलिए आज थोड़े में ही कह रहा हूं।

श्री उपसभापति : आप 15 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री नत्थी सिंह : दूसरी बात मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि छोटे लोग गरीब लोग ही गांव में रहते हैं। शहर में भी रहते हैं, लेकिन शहर के लिए जब हम नीति तय करते हैं गंदी बस्तियों या कच्ची बस्तियों के उत्थान के लिए प्रायरिटी नहीं देते हैं। मुझे मालूम है उपसभापति महोदय, चूंकि मैं एक ऐसे कस्बे से आता हूं, जहां ड्रेनेज की बड़ी समस्या है, हमने उसको सुलझाने की कोशिश की तो जो कहा गया यह तो डेवलपमेंट का काम नहीं है;

इसलिए ड्रेनेज के लिए एल० आई० सी० से पैसा नहीं मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा। मैंने सुना, महाराष्ट्र में दिया गया है। ड्रेनेज के अभाव में मलेरिया और दूसरी बीमारियां फैल रही हैं। ड्रेनेज की व्यवस्था बस्ती को साफ बनाने के लिए करनी ही पड़ेगी।

एक बात जो बार-बार सदन में भी उठायी जाती है वह है हमारी नदियों को साफ रखा जाए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए राष्ट्रीय अभियान बनाना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने देश में जहां इन सब बातों को कर रहे हैं, वहां आज बहस हो रही है कि न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिए। हम जो राजस्थान से आते हैं एक अरसे से इस बात को उठाए चले जाते हैं कि हमारे यहां जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बात को फिर उठाना चाहता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात को कानून मंत्री तक पहुंचाएं। जब राजस्थान बना, सन् 1958 तक हमारे यहां जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच काम करती थी, उसको एक दम हटा कर जोधपुर लाया गया। आज दिल्ली से कलकत्ता तक जाने में जो समय लगता है उससे ज्यादा धोलपुर से जोधपुर जाने में समय लगता है। इसलिए न्याय सस्ता और सुलभ देना चाहते हैं तो जैसे देश के अनेक प्रदेशों में बैन्चेज हैं, यू० पी० में हैं, केरल में हैं, तो हमारे यहां क्यों न हों? हमारे यहां के बैन्च को एक तरीके से गैर-कानूनी ढंग से तोड़ा गया है, इसको करने का अधिकार नहीं था। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान की इस बात को निश्चित रूप से सुना जाना चाहिए और जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। वह यह है 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए हम कमेटियां बना रहे हैं, जिला स्तर पर। ठीक है, बनाएं। लेकिन सारा काम अफसरों पर छोड़ रहे हैं। परन्तु इसमें एक रूरल डिपार्टमेंट है जिसके लिए आप पैसा दे रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही हमारे ग्राम पंचायत की व्यवस्था है? क्या इस व्यवस्था को लकुवा मार गया है? 1959 में मैं पंचायत समिति का प्रधान था और यह हमारा सौभाग्य था कि पंडित जवाहर लाल नेहरू हमारे नागोर शहर में आये थे और उस समय उन्होंने विकेन्द्रीकरण का दीपक जलाया था, लेकिन अब विकेन्द्रीकरण की बात दिखलाई नहीं देती है। 12-13 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाते हैं। पहिले जो पंचायत समितियां होती थीं वे एक तरह से मिनिचर असेम्बली की तरह काम करती थीं। वहां पर लोग सवालों का जवाब देने में घबराते थे। अब हालत यह है कि ग्रामों के लिए न सफाई के लिए पैसा दिया जाता है और न ही दूसरे कामों के लिए पैसा दिया जाता है।

जब एग्रिकलचर पर सदन में बहस हो रही थी तो उस वक्त मुझे बोलने का समय नहीं मिला। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पंचायतों के चुनाव कराने के बारे में बार-बार कहा गया, लेकिन चुनाव नहीं कराये गये। मेरा कहना यह है कि बार-बार कहने से कोई मतलब नहीं निकलता है। इसके लिए तो एक निश्चित प्रोग्राम बनाया जाना चाहिये और सब जगह पंचायतों का चुनाव कराया जाना चाहिए। हम इस देश में श्री प्रकाश वीर शास्त्री की पार्टी की तरह यूनिटरी सिस्टम नहीं चाहते हैं, हम तो इस देश में फैडरल सिस्टम चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि केन्द्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। लेकिन साथ ही ग्रामीण स्वराज्य का जो स्वप्न देखा था, वह हमें पूरा करना चाहिये ताकि ग्रामीण

[श्री नत्थी सिंह]

पंचायतें और सहकारी समितियां स्वावलम्बी बन सकें। अगर ये संस्थाएं मजबूत होंगी, तो हम जो बीस सूत्री कार्यक्रम है उसको अच्छी तरह से कार्यान्वित कर सकेंगे और सब समस्याओं का भी मुकाबला कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI VISWANATHA MENON (Kerala) : Sir, I take this opportunity to highlight some of the important projects pending sanction from the Central, Government in my State, that is, Kerala State,

Sir, the Cochin port is considered to be the 'Queen of the Arabian Sea". But, unfortunately, now the present position of the Cochin port is that it is in a very pitiable condition. Sir, in 1970 the proposal to have a super-tanker berth in Cochin was accepted by the Cabinet, but till now it is only a dream. Sir, we hear various rumours that our project for a super-tanker berth is being shelved by the Transport and Shipping Ministry. Sir, it is really not in the interests of that region. I submit, Sir, that the production in the shipyard and the repair work along with production in the shipyard, will be greatly helped if a supertanker berth comes up, because many ships big ships, can come into our shipyard, the Cochin Shipyard. But if the supertanker berth scheme is being shelved, it will naturally affect our shipyard also. Sir, as a long-term policy and with an idea to have national works, my humble submission is that the super-tanker berth in Cochin port must be taken up.

Sir, in this respect, I wanted to draw the attention of the House to the fact that we hear that some Committee has been formed by the Cabinet to go into the question whether a super-tanker berth is essential, because in Bombay High we have found oik Sir, it is a very welcome thing that we have found oil in Bombay High. But even if we concede that, the point that I want to stress is that our super-tanker berth will be useful not only for oil but also for fertilisers and other such things. It will also greatly help the repair work. Sir, I want to draw the attention of the honourable House to the fact that Cochin is the only major port in India which did not have any development programme during the last 15 years or more.

During the 4th and 5th plans, huge plan outlays have been indicated but in actual working it has turned out that only a small fraction of originally indicated figure has been made available mainly because the major portion of initial outlay was for the Super Tanker Oil Terminal Project and the Dry Dock both of which have been indefinitely delayed. The total 4th plan outlay for the port was Rs. 18 crores out of which Rs. 8.73 crores were earmarked for Super Tanker Oil Terminal Project. As the Super Tanker Oil Terminal project did not materialise, naturally the profonnance fell drastically. Again in the 5th plan also the original provision is Rs. 36 crores of which about Rs. 24 crores is shown as earmarked for Super Tanker Oil Terminal Project. If the present organised move in influential quarters to delay this project happens to succeed, the fate of the Fifth Plan may also be better imagined than said. I do not want to criticise the Government at this stage because this question is being examined by a high-powered Cabinet Committee. My humble submission is that it is not only in t! e interest of Cochin or Kerala, but it is in the interest of this nation that this project must be speeded up and the Cochin port must be given its due.

Sir, I also want to speak on other points. I want to speak about our traditional industries. Kerala is a land where we produce cash crops that fetch foreign exchange. Our traditional industries like coir, cashew and handloom are in a deplorable condition. Unfortunately, some kind of controversy has been created between the State Ministry and the Centre Ministry on the question of coir. 1 am not going into the merits of this controversy. But I want to stress that the coir workers in Kerala are really starving. Coir industry is earning crores of rup worth of foreign exchange for the Cen exchequer. Therefore, the industry must be saved. The scheme that was formulated by the Kerala Government has been sanctioned by the Central Government. Now, it is said that the amount has been cut short. Now the Central Government is going to

give only two crores of rupees. That is nothing. It cannot do anything. It should be done in a phased manner and we have given our detailed programme to the Central Government. That programme has got the sanction of all the political parties and all the trade unions in Kerala. Some sort of misunderstanding has been created and some controversy has come up between the Centre and the State. Sir, the interest of the people of Kerala and the coir workers is above all these things. The coir workers are half-starving. Those workers must be saved and the industry must be saved. Sir, my humble submission to the Government through you is that the Coir Workers' Scheme must be accepted in toto. We are not asking for any grant. We are asking for only loan and that loan of 7 crores of rupees must be given to the people of Kerala. On this question, 1 want to stress once more that the interest of the nation is also affected because coir earns foreign exchange. I hope the hon. Minister will be aware as to how much money the Central exchequer is getting from coir. I request the Government through you that the scheme must be accepted. Sir, coming to the other points, I want to draw the attention of this hon. House to the plight of the coconut growers in Kerala. Sir, the name 'Kerala' itself means land of coconuts. Our main agricultural product, coconut, is losing its money value in the market. 1 do not want to elaborate it but my humble suggestion is that this coconut farming must be saved, this agricultural product must be saved. For that purpose, we request a board, a coconut board. Though 1 am speaking only on behalf of Kerala, coconuts have become an important factor in Karnataka, Tamil Nadu, Pondicherry, Gujarat and many parts of the country. So, a coconut board must be established just like the Rubber Board for rehabilitating coconut plantations in this counrry. Some kind of subsidy and help must be given by the Centre. So. on these three points, I request the Government of India that they should come forward and take up the matter seriously and consider it, and have a sympathetic approach towards a backward State like Kerala, which is the southern-most State, and it should not be neglected.

Sir, I do not want to go into any controversial things. All these three projects I have placed before this hon. House are projects taken up or supported by all the political parties in Kerala. So, my humble submission is that it should be one of the grounds, and these projects must be sanctioned.

Coming to the question of rice, Sir, the other day, while replying to the discussion on the Agriculture Ministry, Mr. Jagjivan Ram said that the people of Kerala are now changing their food habits and they are happy to get wheat. Sir, I do not want to say that it is untrue. But to put it like that is not correct. Sir. We are getting only four ounces of rice. So, naturally, we are forced to take wheat. And we are prepared to take wheat. I am not saying that we are not prepared to take wheat. But, why not give us some more rice? Rice is being produced and it is reported in the newspapers that godowns are not available for keeping the foodgrains. So, why don't you give more rice to the people of Kerala? Instead of four ounces, give them 12 ounces of rice. . .

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ (Himachal Pradesh) : He said that it was in addition to the local production. You are getting four ounces...

SHRI VISWANATHA MENON : Sir, my friend has brought up this question of local production. On the question of local production, the difficulty is that we are not producing rice much. Our land is being used for cash crops, and the benefit of the cash crops, by way of foreign exchange, is being taken, by the Centre. Rubber, cardamom, pepper and all these things are produced, and the money is coming to the Centre. . . .

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : We have all praise for that.

SHRI VISWANATHA MENON : Naturally, I think, you will not ask me to cut out all these and put rice in their place because it is the nation's wealth that we are making. We hear reports that a large quantity of rice is there. So, my humble suggestion is that the ration in Kerala must be raised so that the people of Kerala will have some relief on this particular question.

Then, coming to the last point, Sir, I do not know why such a stand has been taken against the Opposition in Kerala, particularly my Party. The Marxist Party is being attacked here. More than 110 detenus are there under the MISA. What

[Shri Viswanatha Menon] is their crime. I do not know. Now, the hon. Home Minister is present in this House. I take this opportunity to appeal to him that this kind of attack is unwarranted. Most of our leaders are in jail. Most of our Party workers are in jail. We are the biggest opposition party in Kerala just as in other parts of India the Jan Sangh or any other party may be the main opposition party. In Kerala Communist Party Marxist is the main opposition party. This party is not being allowed to hold any meetings or conduct any trade union activity; they are not allowed to move about and they are all kept in jails. *(Time bell rings)* Almost all our top leaders except Mr. E. M.S. Namboodiripad and Mr. A. K. Gopalan have been kept in jails. My humble submission is that it is high time that we stopped curtailing the freedom of the opposition in the name of the emergency in Kerala. I request through you, Sir, that these comrades must be released and normal situation mustbecreated so that we can go for elections because the duration of the present Assembly has been extended by six months. I request that a fresh poll must be conducted in Kerala with full freedom and I request the Home Minister to . take initiative in the matter.

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : Mr. Deputy Chairman, Sir, I support the Bill under discussion because this contains an estimate of about Rs. 25 thousand crores for meeting the necessary expenditure of the Government for the year 1976-77. I do not have much to say about it except that I fully support this Bill.

I take this opportunity to congratulate) the Prime Minister and through her the Finance Ministry and other concerned Ministries for the economic measures taken by them as a result of which the esteem of our country has gone very high in the eyes of the world. Hon. Members must have seen in the newspapers of yesterday and the day before yesterday that the World Bank has all praise for the progress that we have achieved in the economic field. Domestically alsowehaveagreatsatisfactionbecause j the value of the rupee is increasing. The value of the rupee in March, 1975 was 30 -47 paise and its present value is 34 -91 paise. This means that there is an increase of about 14% in the value of the rupee. In the matter of consumer price index also, it is a source of great satisfaction to almost every one in the country, especially to the weaker sections of the society, to note that our consumer price index figures have gone back to the level of 1974 figures. The consumer price index figure in 1974 was 286 and in 1975 it had gone up tothe.level of 311 or something like that but it is again 286 now. These are the things of which we can be rightly satisfied and proud. As a result of all these things, the foreign agencies are coming forward and thinking in terms of giving us more aid. Even though we do not beg for that they are themselves doing that in their own interest and in our interest too. The Aid India Consortium which has got 19 countries represented on it is thinking in terms of giving more aid to us. These are all matters of which we can be rightly proud and this is a well-deserved appreciation of the work done by our Prime Minister and her Government. Now, Sir, we can sanction this amount of about Rs. 25,000 crores. For us, as Members of Parliament, it is a point to consider as to what should the strategy to spend this amount in thecountry so that there is more and more appreciation for the work done by the Government and there is more and more satisfaction to the people in the country. As far as I think, the strategy should be that our way of spending should be such that there is more and more satisfaction among the people about our way of spending and our wisdom in spending. It is the way of spendingthatmay bringabout restlessness or criticism among the people. For example, if we spend lavishly and unwisely and with a sense of authority, the people do not feel happy. But if we spend with a sense of prudence and keeping in view the pocket of an average man in the country from where we draw our revenue, then the people feel happy, so, we should devise ways and means in our ways of spending so that people feel satisfied and there is praise and there is also a saving.

Then, our strategy should be to see that we do not spend all this amount of Rs. 25,000 crores till the end of the year. Everybody knows that there is a deficit of Rs. 320 crores in our Budget. Our aim should not be to spend each and every penny that is sanctioned by Parliament through this Appropriation Bill. Our strategy should be to try to save as much as possible so

that this gap of Rs. 320 crores is made good , to some extent by the end of the year. There can be extraordinary situations or there may be circumstances when we have to spend more but, generally, our strategy should be to save as much as possible so that this, minus trend in the Budget is made good by the end of the year. In our present system it happens that those in charge of spending, go on spending with the idea that they have to spend the whole amount by the end of the financial year and if that is not spend, they are afraid that they will be taken to task. The result is that they rushtospendjthe money before 31st of March. Sometimes they even prepare cheques for payments in advance and keep themin their safecustody for payment later on so that the amount is shown as having been spentwithinthefinan cial year. If such a fear is removed from their mind and if their efficiency is not i judged by their capacity to spend, Ithink, the situation can improve considerably. We should not insist on their spending the sanctioned amount within the financial year. Therefore, this sort of attitude in spending public money needs rethinking and evision. These are the measurses that require consideration so that people have greater satisfaction. Our strategy should also be *to* see that our way of spending generates more and more employment to the people. If we go on spending without keeping this factor in view, there will be dissatisfaction among the people. Our strategy should be to save as much foreign exchange as possible. I do not say that these are new things. Something is being done in this regard. But we should lay more and more emphasis on these things. Apart from giving emphasis to these things, we should also work in a planned manner.

For example, in the various public undertakings, vast powers of spending have been given to the officers. They feel that there is no check on them. Here, I would suggest that we should do somethingsothat an impression is created in the minds of the officers vested with vast powers of spend ing that there is somebody to check on them. At present, there are so many committees advisory committees, development committees at the district level, grievances committees and so on. I would suggest that there should be only OiJe council at the district level to look after these things in a methodical manner 4—M238 RSS/76

so that there is effective control overspending. If there is a council at the district level, it would be able to minutely supervise the implementation of the various measures initiated by the Government and to see that the implementation is according to the policies laid down by the Government. For example, the public works department incurs expenditure on the development of roads. This council should go through each and every item of such expenditure so that those who are vested with vast powers of spending feel that there is somebody to oversee them. This is a point which should be considered. I am not in favour of having so many com-mittees which would burden the district administration in regard to holding of meetings and so on. 1 feel that there should be a single body at the district level which would be able to look after the implementation of various measures of the Government and keep a watch over the spending. This is a point which concerns all the Ministries, particularly the Finance Ministry.

Another point is about employment generation. This is a part of the planning process and I need not say much on that. Foreign exchange saving is also another important matter which I have mentioned.

I would also say something about the Members of Parliament. Apart from the privileged people, there are also other ordinary people, weaker sections of the society, who come into Parliament. When they retire, they find it very difficult to maintain themselves. I have seen many such persons. This was also mentioned by one of our "friends yesterdsay. So, it appears very reasonable that some sort of pension should be given to Members of Parliament—and I would go to the extent of saying that Members of the State Legislatures also be given some pension—so that they can pass their life after retirement from Parliament without much difficulty. Of course, it will not be a retired life because people who are in public life never retire; they will be doing some public work; they will be doing something to carry on the policies of the Government, whichever party they may belong to. After all, when they get something from the Government, they can surely see to the proper functioning of the Government and a proper order in the society. So, Sir, I think the Finance Minister or whichever Minister is in charge of it should think in

[Shri Jagan Nath Bhardwaj] terms of bringing forward, asearly as possible, a Bill to provide pension for the Members of Parliament.

{Time bell rings)

Sir, 1 would request for two or three minutes more. Sir, I belong to Himachal Pradesh. Yesterday, my friend from Himachal Pradesh spoke and he stated that out of Rs. 500 crores only 10 lakhs have been provided for our State. This is a very poor help to a State which is already poor and - backward. Sir, how can it develop properly if it is not properly helped by the Central Government ? The planners know that something should be done for the backward and hilly areas but the amount of grant given to Himachal Pradesh is very poor, if such be the grants given to poor and backward areas in the country how can they come up to the proper standard ? *(Time bell rings)* Only half a minute more, Sir.

Sir, in our State there is no addition to railway line. After independence, not even a kilometre of railway line has been added in Himachal Pradesh. It is very necessary in the interests of developing the potential and building up the necessary infrastructure in this well-deserving State that the Railway Ministry should provide at least some money. *(Time bell rings)* I require only one minute more, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, Mr. Bhardwaj. At this rate we cannot carry on.

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : There is one important point, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I am sorry, I am calling the next speaker.

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : Only one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I am very sorry because if every Member were to do like this, saying one minute, two minutes and take about five to ten minutes each, then there will be a big list of speakers left out.

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : All right, Sir. Thank you.

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे (नाम-निर्देशित) : माननीय उपसभापति जी, आपने इस विधेयक पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। चूंकि, जाहिर है, समय जो आप मुझे देंगे वह कम है इसलिए मैं उन्हीं बातों पर रोशनी डालना चाहूंगा जिन पर और वक्ताओं ने रोशनी नहीं डाली ।

श्रीमन्, आज शहरीकरण की वजह से शहरों की आबादी बढ़ रही है और उसके कारण बहुत सी समस्याएं खड़ी हो रही हैं जिनका मुकाबला आसानी से नहीं किया जा सक रहा है। यद्यपि इस विधेयक में ऐसी तमाम बातें हैं, ऐसे प्राविजंस हैं, प्रावधान किए गए हैं, कि जिनसे उन समस्याओं का पूरी तरह मुकाबला करने की ख्वाहिश दिखायी देती है मगर चूंकि समस्याएं इतनी विशाल हैं, इतनी बड़ी हैं कि वे पकड़ में आना और उन्हें सुलझा सकना मुशकिल मालूम होता है। शहरों की आबादी जिस कदर बढ़ रही है, उसका नतीजा क्या है ? उसका नतीजा यह है कि हर जगह समस्या पैदा हो रही है, पानी की, वाटर सप्लाई की अभी उस दिन इस सदन के सामने एक सवाल पैदा हो रहा था कि गंगा और जमुना के संगम में ऐसा गन्दा पानी सलेज वाटर डाल दिया जाता है, कि जिसकी वजह से संगम का जल विषाक्त हो रहा है।

इत्तिफाक से चूंकि मैं इलाहाबाद म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन रहा और वहां के म्युनिसिपल कारपोरेशन का मेयर भी रहा और इसी वजह से मैं वहां की दिक्कतों को अच्छी तरह से जानता हूं । सवाल यह है कि जहां यह सलेज वाटर भेजा जाता है जमुना के उस पार, उसको भेजने में दिक्कत पेश आती है। रेलवे वालों ने कह दिया है कि जो रेलवे का जमना ब्रिज है उसमें 43 इंच के दो पाइप लाइन के अलावा वह ज्यादा बोझ बरदाशत् नहीं कर सकता है। परिणाम यह हो रहा है कि अगर जमुना के पार यह सलेज वाटर नहीं जा सकता तो फिर उसे जमुना में डालना पड़ता है। इस सलेज वाटर को डालते वक्त इस इस बात का विशेष तौर से ख्याल रखा

जाता है और उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि उसमें कोई दोष न रहे और उसके दोषों को मिटाने के बाद ही इसे जमुना में डाला जाता है।

इलाहाबाद के शहर में तो पानी दिया जाता है जमना में बहुत ऊपर से लाया जाता है जिसकी वजह से इसमें कोई दोष नहीं होता है। जल का जो एनेलैसेस किया जाता है उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं और ऐसे रिजल्ट नहीं आते हैं जिससे यह जाहिर हो कि वह पानी दूषित है। मैं जो बात कह रहा हूं वह इसलिए कह रहा हूं कि आज करीब करीब हर बड़े शहर में पानी की दिक्कत होती है चाहे वह अहमदाबाद हो, चाहे बंगलौर हो, चाहे मद्रास हो। इन शहरों में बहुत दूर से पानी लाने की जरुरत होती है। अगर कोशिश यह की जाय कि जो देश के बड़े शहर हैं उनकी आबादी सीमित की जाये बाहर के देश जिन्हें देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है उनके सम्बन्ध में मैं अपना अनुभव बतलाऊंगा। जब मैं सोवियत रूस गया था तो मास्को शहर के गर सोवियत चेयरमैन थे, उनसे मैंने पूछा कि आप आबादी को किस तरह से कंटेन करते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हमने सोवियत नगरों की जो नैचुरल ग्रोथ है, उससे अतिरिक्त हम आबादी को बढ़ने नहीं देते हैं। हमने बड़े बड़े शहरों के चारों तरफ सैटलाइट टाउन बना दिये हैं जहां तीन सौ से एक हजार या अधिक मजदूर जहां काम करते हैं ऐसे कारखाने हमने मास्को से हटा दिये हैं। ये सेटेलाईट टाउनशिप बड़े शहरों से 99 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं बड़े बड़े शहरों के चारों तरफ इस तरफ से सैटलाइट टाउन बना दिये हैं जहां पर हर प्रकार की सुविधा वहां के रहने वालों को मिलती है। इसका परिणाम यह हुआ कि मास्को शहर की आबादी बढ़ने नहीं पाती और न ही हम उसे बढ़ने ही देते हैं।

श्रीमन्, आज दिल्ली की कैफियत क्या है? आज दिल्ली की कैफियत यह है कि इसकी आबादी बढ़ती ही चली जा रही है। आबादी के बढ़ने के साथ ही साथ हमने इसके बहुत आसपास इंडस्ट्रियल टाउन चाहे वह गाजियाबाद का हो चाहे फरीदाबाद की स्थापना कर दी है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि दिल्ली शहर धीरे धीरे फैलकर इन शहरों के साथ मिल रहा है। इससे स्थिति ऐसी आ सकती है कि बहुत बड़ी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो सकती हैं। मान्यवर, आज इन तमाम समस्याओं को देखते हुए हमें यह भी देखना होता हैं कि जहां आबादी बढ़ती है वहां स्लम भी बढ़ जाते हैं और स्लम्स बढ़ने की वजह से तरह तरह की दिक्कतें पेश आती हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है उसने मकान बनाने की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। लेकिन आज हाउसिंग की क्या कैफियत है? आज हाउसिंग की यह कैफियत है कि जहां हम मकान बनाते हैं उनमें सामाजिक लक्ष्य हमारे सामने नहीं रहता है। हमारे सामने यह लक्ष्य रहना चाहिये कि हम इस देश में सोशलिस्टिक पैटर्न का समाज बनाने जा रहे हैं, हम इस देश में एक सोशलिस्टिक सोसायटी कायम करने जा रहे हैं, लेकिन हाउसिंग की जो हमारी पालिसी है, मकानों के जो नक्शे हैं, वे इस सोशलिस्टिक सोसायटी के मुताबिक नहीं बनाये जाते हैं। रूस में जो मकान बनाये जाते हैं या सोशलिस्टिक कंट्रीज में जो मकान बनाये जाते हैं, वहां 60 फ्लैट्स का एक ब्लाक बनाया जाता है। उस ब्लाक में एक मामूली वर्कर भी रहता है, मिल का जनरल मैनेजर और एक स्किल्ड मजदूर भी रहता है। वहां पर लोगों की हैसियत के मुताबिक अलग अलग तरह के मकान नहीं दिये जाते हैं। एक ही ब्लाक के अन्दर किसी मिल का जनरल मैनेजर भी रहता है और एक मामूली मजदूर भी रहता है। अगर जनरल मैनेजर के खानदान में तीन मैम्बर हों तो उसे एक रूम का टैनेमेंट

[श्री विश्वम्भर नाथ पांडे]

मिलता है और अगर किसी मजदूर के परिवार में दस मैम्बर हों तो उसे चार रुम का टैनेमेंट, चार कमरे वाला घर मिलेगा ।

और किराया है फोर परसेन्ट आफ दि पे । वहां कैफियत यह है मजदूर हो या जनरल मैनेजर वह महसूस करता है कि हम एक सम्मिलित परिवार के, एक तरह के लोग हैं, यह नहीं कि पियन छोटी हैसियत का आदमी है और सेक्रेटरी बड़ी हैसियत का आदमी है। यह कैफियत वहां पैदा नहीं हो पाती। हमने तरह तरह के तजुर्बे करके, मकानों के तरह तरह के नमूने बना करके सोसायटी को फाड़ रखा है। उसने इतने मतभेद पैदा कर दिये हैं कि मैं चाहूंगा कि इस पर जल्दी गौर किया जाय और हम चाहते हैं कि हमारी योजनाओं में यह सोशल डिस्टिंग्शन्स पैदा न होने पायें ।

1 P.M.

मान्यवर, यहां लोगों ने जिक्र किया खेती की पैदावार का। लेकिन मैं जिक्र करना चाहता हूं खेती की पैदावार के अलावा उन कोमल फूलों का, बच्चों का जिनको हम तरह तरह की तालीम देते हैं। खेत में तो हम फर्टिलाइजर देते हैं लेकिन इनको जो फर्टिलाइजर हम देते हैं वह तालीम होती है, लेकिन आज जो तालीम दी जा रही है उसने उनके दिमाग को गन्दा कर दिया है। बचपन से उन्हें तालीम दी जाती है इतिहास की, तारीख की, उसमें ऐसी गलत बयानियां भरी रहती हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग गन्दा हो जाता है और राष्ट्रीय एकता जैसी चीज यहां कायम नहीं हो पाती । मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं । छत्रपति शिवाजी के कैरेक्टर को कम्युनल कैरेक्टर कह कर पेश किया जाता है। लेकिन श्रीमन्, शिवाजी का साम्प्रदायिक कैरेक्टर नहीं है। वह राष्ट्रीय चरित्र का महान नेता था। कैफियत यह थी कि छत्रपति शिवाजी के दादा प्रसिद्ध मुस्लिम संत शाह शरफ के बहुत बड़े भक्त थे। उनके दो बेटे हुए। उहोंने बड़े बेटे का नाम शिवाजी के पिता का नाम शाह जी रखा और शिवाजी के चाचा का नाम शरफ जी रखा। शिवाजी के पिता शाह शरफ के आशीर्वाद से पैदा हुए थे जैसा कि उनके नाम से प्रगट होता है। शिवाजी का अंगरक्षक इब्राहीम था। जब वे अफजल खां से लड़ाई करने गए तो इब्राहीम उनका अंगरक्षक बन कर गया। इसी तरह शाहजहां का अंगरक्षक महेशदास था । लेकिन इन बातों को इतिहास में नहीं बताया जाता। शिवाजी का कान्फीडेंशियल सेक्रेटरी शेख हैदर काजी था जो शिवाजी के तमाम रिकार्ड रखता था और जिन पर उसकी मुहर रहती थी । शिवाजी के सैनिकों में, अफसरों में, जल सेना- नायकों में हजारों की तदाद में मुसलमान और दूसरे लोग थे ।

मान्यवर, जरा नज़र दौड़ाइए राणा प्रताप की तरफ। राणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध को साम्प्रदायिक लड़ाई कह कर पेश किया जाता है। कैफियत यह है कि मुगल और राजपूतों की संयुक्त सेना के राजा मान सिंह नायक थे और दूसरी तरफ राणा प्रताप की सेना के नायक थे जालौर के ताजखांन और हकीम खां सूर। एक तरफ मुगल सेना अकबर की तरफ और एक तरफ पठान सेना राणा प्रताप की तरफ। हल्दी घाटी के युद्ध में पठान मुगलों को मार रहे थे, मुगल पठानों को मार रहे थे, राजपूत राजपूतों की गर्दन काट रहे थे। क्या किसी अर्थ में उसको धर्म युद्ध, साम्प्रदायिक युद्ध कह सकते हैं ? नहीं। इसी तरह से पूरे इतिहास की विडम्बना यह है कि हमने लोगों के दिमाग, खासकर बच्चों के दिमाग जहर से भर दिए हैं और आज उन्हीं चीजों को दोहराया जाता है। इस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन कैसे हो सकेगा ?

अब नये शहरों का निर्माण होता है। पुराने शहरों में जातियों के हिसाब से मुहल्ले बनते थे। मुसलमानों की अलग अलग जातियाँ अलग-अलग मुहल्लों में रहती थीं और हिन्दुओं की अलग अलग जातियां

अलग-अलग मुहल्लों में रहती थीं। नये नगरों के निर्माण में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये तमाम बन्धन तोड़ें, जो जातियों और साम्प्रदायों के वाटर-टाइट कम्पार्टमेंट बना कर शहरों को बांट दिया है वे तमाम हदें खत्म हों। तो हमें नगरों के निर्माण में ऐसी भावना पैदा करनी चाहिए कि अगर हम कहीं प्लाट दें, कहीं अलाटमट करें तो इस बात को देखें कि खाली एक तबके के लोग, एक सम्प्रदाय के लोग, एक जाति के लोग एक जगह स्थायी होकर न रहें।

जब हम ऐसा करेंगे तब एक नयी इंटीग्रेटेड सोसाइटी यहां कायम होगी, एक नया इंटीग्रेटेड समाज उस देश में बन सकेगा। मान्यवर, हमें यह देखना है कि हम किस तरह से इस समाज का निर्माण कर सकते हैं? मुझे खुशी है कि हम ने पिछले साल भर के अन्दर, हमारी सरकार ने, हमारी प्रधान मंत्री ने एक नया जोश, एक नया उत्साह, एक नयी दिशा लोगों को दी है जिस की वजह से हम बजाय एक मामूली आय व्ययक के एक परफारमेंस बजट लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन इस पर अमल कैसे होगा? जैसा कि इनीशियेटिव हायर लेविल में है, प्रधान मंत्री जी और हमारी माननीय मंत्री जी जो इनीशियेटिव ले रही हैं वही इनीशियेटिव अगर ब्योरोक्रेसी नहीं लेती, वही इनीशिएटिव अगर सेक्रेटरी के लेविल पर भी नहीं लिया जाता और विभिन्न मंत्रालयों में कोआर्डिनेशन नहीं होता जिस की कि आज बहुत जरुरत है तो बहुत सी चीजें अनकही रह जायेंगी। बहुत सी चीजें पूरी नहीं हो सकेंगी। इसलिये वित्त मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वह इस बात को देखें कि विविध मंत्रालयों में जो कोआर्डिनेशन होना चाहिए वह हो और वह किस तरह से हो इसको वह आपस में बैठकर तय करें। क्योंकि वित्त मंत्रालय है, प्लानिंग कमीशन है और दूसरे विविध मंत्रालय हैं। कैफियत यह है कि अलग अलग फैसले हो जाते हैं। योजना आयोग अलग फैसला कर लेता है और संबंधित मंत्रालय को उस की सूचना तक नहीं होती। तो इस बात को देखना है कि योजना आयोग जो भी फैसला करता है वह फैसला वह संबंधित मंत्रालय से सलाह मशविरा कर के ही करता है।

मान्यवर, मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में बहुत सी पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, गृह उद्योग हैं। कार्पेट का गृह उद्योग है और दूसरे तमाम गृह उद्योग हैं। उन को बड़ी शक्ल देने की कोशिश हो सकती है जिस से बहुत सा फारेन एक्सचेंज हमारे देश को प्राप्त हो सकता है। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा प्रदेश है। योरुप के दो, तीन देशों के बराबर का प्रदेश है आबादी के लिहाज से, लेकिन हमारे वित्त विधेयक में देखा जाय कि यहां के विविध मंत्रालय उत्तर प्रदेश पर कितना खर्च करते हैं, पापुलेशन के रेश्यो के हिसाब से कितना प्रावधान इस में है इस बात को हमें देखना है। वित्त मंत्रालय को देखना है कि उत्तर प्रदेश एक अवज्ञापूर्ण प्रदेश की तरह न रह जाय बल्कि योजना में उस का समुचित हिस्सा हो।

हमारे यहां इलाहाबाद में एक रेडियो स्टेशन है। मिर्जापुर और उस के आसपास जो नया इंडस्ट्रियल कांम्लेक्स डवलप हो रहा है इलाहाबाद का रेडियो स्टेशन उस तमाम कांप्लेक्स को सर्व कर रहा है। लेकिन वहां के रेडियो स्टेशन की जो ट्रांन्समिटिंग कैपेसिटी है वह मुश्किल से एक किलोवाट की है। नतीजा यह होता है कि बीस मील से ज्यादा दूरी पर उस की आवाज नहीं सुनाई देती। तो ऐसा रेडियो स्टेशन रखने से क्या फायदा? यह बात प्रसारण मंत्रालय मानता हैं कि वहां जितना टेलेंट है, जितने आर्टिस्ट वहां हैं, जितने इंटेलेक्युअल्स वहां हैं उतने और दूसरे किसी जगह मिलेंगे तो मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन अगर उस

[श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय]

टैलेंट को दिल्ली ला कर दिल्ली रेडियो स्टेशन से वह चीजें ब्राडकास्ट होती हैं, प्रसारित होती हैं तो वहीं चीजें वहीं से क्यों नहीं प्रसारित हो सकती । इस लिये उस को जरा एक्सटैंड करना चाहिए । मैं वित्त मंत्रालय से बड़े अदब से प्रार्थना करुंगा कि वह इस बात को देखें कि प्रसारण मंत्रालय इस बात को ध्यान में लाये कि कम से कम इलाहाबाद के रेडियो स्टेशन की क्षमता, प्रसारण क्षमता जितनी है उस को वह ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करे ताकि कम से कम सौ, डेढ़ सौ मील के इर्द गिर्द उस की आवाज पहुंच सके और जो मकसद है उस को वह पूरा कर सके और पूरे क्षेत्र में उस की आवाज पहुंच सके और बहुत सी समस्यायें हैं जिन की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि वह ऐसी समस्यायें हैं कि जिन पर विस्तार से अपनी राय जाहिर करने का मौका मैं किसी दूसरे वक्त में लूंगा । फिलहाल मैं समझता हूं कि जितनी बातें मैंने कही हैं वह यथेष्ट हैं और वित्त मंत्रालय अगर उन पर ध्यान देगा तो बहुत सी समस्यायें इससे हल हो सकती हैं ।

माननीय, उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभार मानता हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपने विचार इस सदन के सामने रख सकूं ।

धन्यवाद ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The house stands adjourned till quarter past two.

The House then adjourned for lunch at fifteen minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at eighteen minutes past two of the clock, Mr. Deputy Chairman in the Chair.

THE APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1976—*contd.*

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY (Assam) : Sir, I rise to support this Bill and 1 want to draw the attention of the Government to certain issues and also 1 want to put forward some suggestions for the consideration of the Government.

Sir, we are discussing this Bill for the last two days and many of the honourable Members here have spoken on the implementation of the 20-point economic programme, particularly on the development of agriculture. To my mind, the development of agriculture does not depend on the 'pricing policy alone which many of the Members dwelt upon as if some high prices for the agricultural commodities will lead to the development of agriculture. What I feel is that, today, in this country, it is not the price of the produce which is important but what is important is the right of the real producers on their produce. These days, Sir, those who actually till the land and who sweat and toil and produce, do not have any right on their produce a tall. Mainly, the landlords who actually own the la^d and do not till this land reap the benefit out of toils the real tillers. Now the present policy of the Government of taking this up as a time-bound programme, which has to be completed by the 30th June, I think, is the best method by which we can give the real producers, the farmers, the right on their produce. Sir, if this is done, then, I believe, that the real tillers or farmers having a right on the land, will be more enthusiastic in increasing the production, and I believe that production will increase definitely.

Sir, while implementing these land reform measures, certain things have come to light. We find that a vast area of land has been transferred through what is called 'benami' transfer. We have to find out these benamdars' and the proprietors who 'have transferred their land in the name of benamdars'. Sir, now it is being said that these 'benamdars'will be made owners of this 'benami' land.

Sir, what I feel that is \\ will not solve the problem, because these'benamdars' are of two kinds. One section is of people who are stooges in the hands of the landlords and the other section is non-existent persons, *'X',* 'Y' or 'Z' or some name. And this has taken place with political pat-

ronage of a section of corrupt politicians and with the connivance of corrupt revenue officials. Sir, if these 'benamdars' will be made the owners, if this policy is adopted by the Government, 1 think it will help those corrupt officials and also corrupt landlords who have made these 'benami' transfers. It will help them and they will perpetuate this corrupt practice. 1 think some steps should be taken to find out the real proprietors of lands which have been thus transferred, otherwise the revenue officials who are in league with the landlords will never know what is the real position. The land will be in the name of the landlord who will pay the revenue and will take the yield for himself. Sir, this will create a new problem, Now we have adopted the policy of fighting black money. A bulk of this black money has been invested in land. It has become a way of investing black money. This will create further black money. That will not be on record, the in come from this land will not be recorded anywhere and it will become a further source of accumulation of black money. Sir, the Government should try its utmost to catch these 'benamdars' and take action against these corrupt officials who have colluded with these landlords and also those who have transferred their lands in the names of 'benamdars'. They should also be punished. This is one thing, Sir.

Sir, we have taken land reform measures. But these landless people will not be able to take possession of the land. Tenancy rights and laws have been amended in many States to give rights to the tenants and cultivators. Even then, large scale eviction of cultivators is taking place everywhere. Effective measures have to be taken. The motivation of our revenue officers and the Police is not to side with the farmers but to side with the landlords because most of them come from the propertied classes and they have a mental affinity with the propertied classes. As a result of this, when these evictions take place, they normally side with the landlords and not with the cultivators. Therefore, the Government should take steps to change this motivation of the officers who are involved in the implementation of the tenancy and land reform laws.

Then Sir, we have banned bonded labour. In our forest manuals itself you will find that in forest villages, any adult male person who dwells in any forest village has to do some free labour for certain days. That is compulsory. I raised a question in this House and the labour Minister replied that no State Government has reported any such system. But, Sir, it is there in the forest manuals. It does not require any reporting by anybody. No steps have been taken so far. I would request the Government through the Deputy Minister who is present here that some timely steps should be taken. When bonded labour has been abolished, this system of free labour should also be abolished. It can be found out from the forest manual itself. I think it is available in the Central Secretariat Library. There is a system that whosoever resides in a forest village he has to do some free labour for some days.

DR. RAMKRIPAL SINHA : In which State ?

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: There is a national policy on forestry. It is there. The next point is about the development of Assam. Take the case of Assam. If tourism and sericulture are developed, then it will be able *to* gi\e some direction to the economy there. Whatever planning we do, we do not take into consideration the local conditions. The result is that whatever planning we are doing, the basis is *adhoc,* some industry here and some industry there, one project here and one project there.

So, it does not have any total effect on the economy. Sir, so far as the development of economy in Assam is concerned, what 1 feel is that mass-scale involvement of people can only be possible if we develop sericulture, tourism and weaving industry. But these three sectors are being neglected in all the Plans. They were neglected in the last four Plans. In the Fifth Plan, some priority has been given to sericulture but no stress is being laid on the development of tourism there. Even when the State Government comes with a proposal of five or six lakh rupees for the development of tourism, they do not get it. My only submission is that whatever allocation of resources in the Plans is made, the local conditions should be taken into consideration.

[Shri Nripati Ranjan Chaudhury]

Lastly, Sir, I want to draw the attention of the Minister to the fact that Assam being an economically backward State, no priority has been given in the industrial sector. Sir, we have only one public sector refinery. That is the only public sector industry in our State. Two paper mills were sanctioned for Assam. Since 1967, nine years have passed but these paper mills have not come to sight. Regarding the Bongaigaon refinery, now the buildings have come up but we do not know when it will be commissioned. So, my request to the Government will be to kindly expedite these projects so that within this plan period, within the Fifth Plan period, these projects can come up. Last of all, Sir, . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You have already made your last point.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY : Only one point more, Sir. I want to draw the attention of the Government to the Asssam Government's demand for declaring Assam a backward State. Sir, the Assam Government has demanded that Assam should be declared a backward State. Unless it is declared a backward State, bank financing to the co-operative societies for the development of agriculture and agro-based industries in the rural areas cannot take place. In order to extend this facility to the rural folk of Assam. I think, the Assam Government has made a demand like that. I would request the Government to concede to their demand. Thank you, Sir.

SHRl KRISHNARAO NARAYAN DHULAP (Maharashtra) : Mr. Deputy Chairman, Sir, with your permission, I will now take part in the deliberation on the Appropriation (No.4) Bill, 1976, to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial yea$_r$ 1976-77.

Sir, much has been said about the 20-point programme, after the declaration of the emergency and its implementation. To my mind, it appears that the urgency which was felt at the time of the proclamation of the emergency is no-where to be seen at present. Instead of that urgency and that thrust, laxity is prevailing and a sense of complacency has risen at different levels. For example, Sir, it has been said about the establishment of regional rural banks that it was a sort of panacea for all the problems which the rural community is facing in this country. For the freed ibonded labour, they say that Rural banks have to be established and that they will get financial help from these banks. It has been said that for the marginal farmers, small farmers and agricultural labourers and for all activities connected with the agricultural development in the rural areas, the establishment of regional rural banks will be sufficient to meet their requirements and solve their problems. Today also hon. Minister, Shri Pranab Mukherjee, referred to the establishment of regionl rural banks. How many banks have been set up since the 2nd October, 1975 ? The reply has been given today is answer to one of the questions. Only 19 banks have been established in ten States. Shri Choudhury pleaded for his State of Assam to be declared as a backward State. He is not here now. The names of the] States in which these banks have been established are : Andhra Pradesh (1), Bihar (2), Haryana (2), Jammu & Kashmir (1), Karnataka (1), Madhya Pradesh (1), Orissa (2), Rajasthan (1), Uttar Pradesh (6) and West Bengal (2). These are the regional rural banks established since 2nd October, 1975. And, Sir, for small farmers, marginal farmers, agricultural labourers do you know how much money has been advanced by these 19 banks? The total money has been advanced by these 19 banks is Rs. 29-32 lakhs. And, Sir, do you know how.,many persons have been benefited? The number of beneficiaries is 7,557. This is the urgency for the rural backward people. For the last six months these banks are working in different States and only Rs. 29 -32 lakhs have been disbursed by them to the needy persons in all the States in which these banks have been set up. This is the urgency, Sir. And, here they have mentioned small farmers, marginal farmers and agricultural labourers but no details have been given. What about the freed bonded labourers ? For them what is the source of money for their rehabilitation? Nothing has been mentioned. Mr. Choudhury, in your State, which is a very backward State, no regional rural bank has been established.

AN HON. MEMBER ; What about Kerala ?

SHRI KRISHNARAO NARAYAN DHULAP : Yes, there are many States where no regional rural banks have been established. There are only ten States where these 19 regional rural banks have been set up since the declaration of emergency or since 2nd October, 1975. This is the sense of urgency for the downtrodden people for whom this 20-point programme has been promulgated by the Prime Minister. So, Sir, if that sense of urgency is removed once for all from the scene of this country naturally there is comlacency and nothing else. Bureaucracy is getting stronger. There is n.o opposition: Nobody is there to challenge. As a result of all that the whole political scene and economic activity in this country which we see now is backed by complacency. Everything is only on paper. Slogans are being given. Papers are full of pronouncements made by the Government but actual implementation is of the type that I have stated. The functioning of the banks which are supposed to be the backbone for the agricultural and rural development of the country, is far from satisfactory.

The second point in which I am vitally interested, which has been referred to by me earlier also on the floor of this House, is regarding the border dispute between Maharashtra and Karnataka. There are, of course, other border disputes also. The then Home Minster, Shri Umashankar Dikshit, had promised the people of this country on the floor of this House that he would see that these border disputes are solved soon. There was a border dispute between Haryana nad U.P. which has been amicably settled. Of course, the Bill has to be brought before this House. There are other disputes still pending. Punjab and Haryana have a border dispute. That border dispute is still there. There is a border dispute between Madras and Karnataka. The border dispute between Kerala and Karnataka is still there and the border dispute between Maharashtra and Karnataka is hanging fire continuously for the last 25 years.

This is high time, Sir, that the Government took up this matter. Border dispute between two countries, between Bangladesh and India can be solved very easily; border dispute between Pakistan and Hindustan can be solved easily but border dispute between Kanataka and Maharashtra is not being solved. It has already taken more than 25 years and it is high time that this dispute was sovled. Whenever a question is put to the Ministry concerned, they give the reply that it is under consideration of the Government. When the question is put again, they say it is under the active consideration of the Government. When we ask for some further details, then they say that in the public interest it is not desirable to divulge the information but the Government is moving very fast. If that is so, then I request the Minister concerned, throgh you, Sir, that he should take immediate steps to see that his long-standing vexed question is immediately solved. It is no use saying as is said in the Home Ministry's report which says that to look into the question of linguistic minorities, the office of the Deputy Commissioner of Linguistic Minorities has been removed froi Bombay and shifted to Belgaum. Simply re-moving any office from one place to anothei is not going to solve the problem. Therefore, Sir, I would request, through you that this problem may be solved immediately.

As far as payment of remunerative prices to the agriculturists for their commodities is concerned, I would urge upon the Government the necessity of paying s remunerative price, if you want to enthuse the farmer of this country to take to agriculture as his way of life. and see thai there is more production on this front Unless and until remunerative prices an given for agricultural produce, you woulc not get more production in the country Sir, I will only refer to a very importaw observation made by Dr. Thomas Balogl who was a professor in Bailiol College Oxford. At the time of formulation o the Third Five Year Plan he observec and his observation still holds good—anc it should be taken note of by this Govern ment and he says :

> "It is essential to give the farmer; complete assurance that they will, if the; increase their production, be able to sel it, and sell it at a profitable price. It i unfair that the peasant should b put into a position where he can onl; lose... If prices are not allowed to soa they must not be allowed to fall eithei To play a game with false dice with th farmers at the beginning of a Thir

IShri Krishnarao Narayan Dhulap] Five Year Plan which demands their utmost contribution for its success, telling them, "Heads T win and tails you lose is not the best way of promoting that enormous increase in agricultural production which is imperative in India."

This observation was made at the time of the formulation of the Third Five Year Plan. Still, Sir, there is some misgiving. The prices are falling in this country and the Government is very jubilant to say that the prices are falling. Prices of what? Prices of agricultural commodities are falling. Prices of industrial products are not falling. Industrialists are making huge profits in this country. If the agriculturists produce more, there is nobody in the market to purchase. Our hon. Minister Jagjivan Ram Babu has said that the agriculturists will not be put to loss and if the prices fall down below a certain level, the Government will come into the market. But that is not the case. In Maharashtra, the State Government has declared that they will not come in the market to purchase whatever surplus of agricultural produce is available in the market. They have not come. They have no money to purchase the surplus from the agriculturists. Whatever agency was there, that is not functioning at all and, therefore, Sir, the prices are coming down. The Government has declared Rs. 105/- as the support price but'in Maharashtra, at present, the price is Rs. 90/- per quintal or Rs. 80/- or Rs. 85/- which is being paid to the farmer. The agriculturists are being looted in the market. Only today, the hon. Minister gave an answer to some of the Members here that the prices of cotton in the market are rising. The prices have risen. But when the agriculturists offered their cotton produce in the market, the prices crashed down like anything. There was no machinery whatsoever to purchase the cotton and therefore, at that time, whatever cotton that came to the market was purchased by the middlemen. The prices are rising now. Who is going to be benefitted by this Not the cotton growers. They are being looted and the middlemen are getting the lion's share. Are we going to keep our eyes closed when lakhs and crores of people are dependent upon agriculture? If this the market situation, it would be very difficult to expect the farmers to produce more. We cannot pursue a policy of 'heads I wiln, tails you lose'. If double standard are applied by the Government in regard to the agriculturists, this would ultimately result in the crushing of the whole agricultural community in this country.

I would like to mention one other problem which is also connected with agriculture. In Maharashtra, there are four agricultural universities. In certain areas like Konkan where paddy is being grown, a pest is prevalent which is known in the local language as "Khodkida". No antidote has been found for this so far. In regard to research, we see that a sum of Rs. 7,53,000 has been allotted for the Department of Agricultural Research and Education. Similarly, payments to the Indian Council of Agricultural Research amount to Rs. 45,50,63,000. This is a big amount, But what have they done in the field of reserch In this connection, I would like to refer to the Draft Fifth- Five-Year Plan-Part II, wherein something has been said about the agricultural research done in the Fourth Five-Year Plan. They have said:

> "The total provision made for agricul-. tural research schemes to be financed by the ICAR was initially placed at Rs. 57 -5 crores and later increased to Rs. 61 -23 crores. Against the above outlay, the pace of expenditure was extremely tardy in the initial years. In the first year of the Fourth Plan, the expenditure was only Rs. 3 -5 crores. There were as many as 64 schemes in which no expenditure was incurred. In the second year, the pace of expenditure somewhat picked up to reach a level of Rs. 6 -3 crores. Even so as many as 16 research schemes did not get off the ground."

This is how research is being done in the agricultural sector for the benefit of the farmers. If this is going to the state of affairs, if this is going to be the performance of the different Ministries as far as agriculture is concerned, agriculture would not get its due in course of time, the whole agricultural commodity would be extinct and there would be no increase in production in this country.

SHRI SRIMAN PRAFULLA GOSWAMI (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to speak on the Appropriation (No. 4) Bill. 1 could not speak

during the general discussion on the Budget and, therefore, I take this opportunity to highlight certain basic things. Sir, 1 would like to lay more emphasis on certain basic problems than on the mathematical side of the Budget or the Appropriation Bill. First and foremost is the administrative machinery which is known as the bureaucratic system. As long back as 1952 when I entered the State Assembly, in my maiden speech in the State Assembly I laid great emphasis on revolutionising the administrative machinery. Again, Sir, when I came to Parliament here, I spoke in 1968 first and later in 1975 also about the urgent necessity of reforming, revolutionising or reorienting the administrative machinery.

Today the emergency has brought discipline in our country and there is a proper atmosphere to implement some of our basic policies to remove poverty from the country. We are supporting the 20 point programme given to us by the Prime Minister and as a first step to make this 20-point programme successful. It is imperative today that we must realise that our outdated administrative machinery or bureaucracy must be reoriented or revolutionised. Although I spoke long ago but today the realisation has come, and our Prime Minister also has laid stress on the reorientation of the administrative machinery, for speedy implementation of the 20 Point Programme.

Sir, many administrative reforms bodies had been appointed and many reports had come, the last one and which took the longest time being the Administrative Reforms Commission headed by Shri Hanumanthaiah. But today, forget those reports don't consult them do not give those reports much consideration. Tf you send it for consideration to the bureaucracy again it will take more time and it will be further Complicated. Decide the basic policy as to how to reform this administrative machinery, how to quicken the process, how to give justice to the needy people, specially the rural people, the poor people, who are so are so long suffering under poverty and social injustice. We need not go by those reports. It is a simple affair Minimise this noting system. At present, with the system which we have inherited from the British, we have so many dealing clerks, so many files with noting after noting so many superintendents, Section Officers, Additional and deputy secretaries attached to each department along with the Ministers. All this takes a long time. Sometimes the files are to be found out on missing you cannot fix the responsibility to anybody for lapses. This noting is nothing but repetition. Sir, I shall read out from what I spoke during the Budget discussion on 20th March, 1968 in the Rajya Sabha itself:—

> "The bureaucracy is growing and growing. We have inherited from the British imperialism an imperialist bureaucracy. Instead of reducing that bureaucracy we have been increasing it, and I am afraid that some day this bureaucracy will grow to such an extent that it will not only kill itself but will kill us also. So it is time that we should be alert to reduce bureaucracy, decentralise the power to village level to the district level, increase the power of district officers in all spheres of administration; let them decide, let them implement; make them responsible. Instead of having so many secretaries, the Minister is sufficient to dictate the policy and one Secretary is enough to carry out and circulate it to the district level."

Now Sir, the present bureaucracy is doing nothing but delaying the process. The multiple levels of consideration must go. Let one officer be made responsible for a specific job, and he must dispose of the matter within a limited period prescribed and if he cannot do it he should be removed from the job or downgraded. Promotion must be on the basis of performance and not on the basis of seniority. Our administrative machinery must be quick, responsive and efficient to deal with matters in the shortest time and render all necessary help and justice and remove the grievances of the people.

Sir, another thing which I have to say is that expenditure on the administrative machinery is very high in India. There are clerks, peons and what not. If a Secretary gets an additional department under him, then all the paraphernalia of peons, typists and so on will be there. I do not know much about the details here but in my State, if a particular head of a department is allotted on an extra head of work, then he will get more typists and office assistants.

[Shri Sriman Prafulla Goswami]

Then he also gets more peons, and those peons are made to work as domestic servants. So the expenditure should be drastically curtailed. The system should be simple and economical.

What is Delhi today ? As 1 said on the last occasion, Delhi has grown so much. In the evening, sometimes I travel by bus and 1 find long queues of office workers. Sometimes it takes them hours to board their buses. Delhi should not be a longer place with bureaucratic system. The officers and staff should go to the villages and districts. Then power must be decentralised to the panchayat level. As I told the House on various occasions, it would be the best method of implementing our policies. Power should be given for-Panchayati *Adalats* to deal with simple cases. The village people need not come to cities or the Capital. They should be able to get whatever they need from their panchayats and co-operatives. Also, panchayati raj should be there.

Then, as 1 told the Parliament earlier also, the present judiciary must be drastically changed because it does not provide the necessary justice. Justice delayed is no justice. There are cases lying pending in courts or 10 to 12 years both in the High Courts as well as in the Supreme Court. The rich people, on getting adverse judgments from the lower courts, can move the High Courts or the Supreme Court. But the poor people cannot affored the expenditure involved, with the result that they do not get any justice. If we want to implement the 20-point programme, first' our judiciary must undergo a drastic change. I welcome the proposed Constitutional amendments. We have made so many amendments to the Constitution. But now the Swaran Singh Committee has focussed some points, and I wholeheartedly support them. There is urgent need not only to re-define our Fundamental Rights, but also to limit the property rights. Under article 226, anything can be brought to the High Court or the Supreme Court and a stay order can be got. This is no justice. Therefore, the Constitution must undergo a change to meet the present needs, to meet the challenge. Otherwise, we connot implement our policies to improve condition of the poor people, we cannot go towards our goal of socialism.

Then, coming to another point, we should give more attention to the rural areas because most of our population, say, 80 percent of our population, lives in village. But for the most time we have been giving more attention to cities because the officers are living there, the rich men are living there, and there are so many amenities available, so many parks, flowers, transport facilities, and what not. But we have been neglecting our villages. Now, it is our Prime Minister who has realised the situation and has given direction in terms of these 20 points to go to the villages in order to implement the policies. Now, there are certain things which the villagers should get. Should they have drinking water first or should we provide water for fountains in parks herein cities? Sometimes, I feel morally guilty to stay here. But then 1 am also continuing like others. As I said, there should be drinking water facilities made available to the villagers. Then, priority should be given to power for rural areas. Panchayats should play their role, as is given in the Directive Principles of the Constitution. When the Constitution is amended, I would request the law Minister to make uniform the concept of law for village Panchayat which could be followed by all the States. 3 p. M.

The Panchayat may not come to the Central List but the Constitution should be amended in such a way that there should be a uniform law by which you can have decentralisation of power. Many of the people, when they become MALS, do not like to give power to the village panchayats ; even in the appointment of primary teachers, the MALS have got their quota. All these things are going on in the name of socialism or whatever you call it. I sometimes wonder many young men speak very often of socialism but in practice, you will find that they are all for the accumulation of wealth, for living in a high standard in the towns and cities and for going in cars during elections, for delivering lectures about socialism and then coming back to towns at night they forget everything. They do not like to stay in Villages with the people. We are freedom fighters of the old type; our conscience always pricks. I am a freedom fighter, left college in 1930 and now of 65 years of age. So, I am speaking with my experiences.

Priorities in respect of villages should be there ; essential consumer goods for the people should be there and each village panchayat should have a two-storeyed house costing about Rs. 40,000 or Rs. 50,000. They should have a co-operative consumers' society there with a godown. They should have .the foodstuffs there. They should have a small library for the cultivators and others along with an office for the panchayat. But today we are not giving priority to one such building whereas we are constructing multistoreyed buildings in cities. I have been pressing our Chief Minister also to give the panchayat a dak bungalow or a two stoTeyed house with C.I. sheets roofings. If you have a store house for Paddy procured from the village, when any emergency comes, you can give that paddy. Now, paddy has to come from a distance of 75 miles or 85 miles and there is the transport problem. Village people are to pay much more than the sale price which they get at the time of sale. Recently, I performed a continuous *padyalra* for four days. I did not come back to my home. I covered about 75 kms. I stayed in the villages and I had rest only for three or four hours a day. Even at 2 -00 a.m. I was visiting the villagers and talking to them. In the Nalbari Sub-Division, I covered five MLA's constituencies. In the rural areas I found that there were many needy, landless people. According to the Government records, there were some lands. But the rich men were occupying them. The poor people were to get the lands but distribution was delayed for about one year. There were manipulations by the revenue staff and by the police. For the last six or seven months during emergency even this is not rectified. They said that they had given applications, to the Minister even, who happened to be from that area. 1 spoke to our Home Minister to expedite the matter who is now entrusted there. The land is limited. But whatever land is available above the ceiling limit, that is not also not distributed to landless cultivators. Many things are not happening; many reports are coming in. The prime Minister knows that some people are very corrupt from top to bottom. Whenever we hear her speeches she says, go to the village level and implement the policies. We are fortunate to have a great Prime Minister who has surpassed her predecessors, who has indomitable courage, conviction and capacity to lead our country towards the goal professed by Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru. She is, like Jawaharlal Nehru, not only our Prime Minister, but our greatest national leader and also a • distinguished, renowned and popular states man of the world.

To-day India's prestige and image has gone high in the world under her leadership. Further the policy of non-alignment and maintaining of peace in the world is ably demonstrated and worked out under her leadership. India is having more and more friends among nations because of her sincerity of purpose and truthfulness to friendship. It is now our imperative and urgent duty and obligation to remove poverty from our country by selfless, sincere, devoted and dedicated hard work under the leadership of our beloved Prime[r]Minister Shrimati Indira Gandhi. Let us take a pledge to fulfil the 20-point programme now and be ready to follow it up with the next steps. Jai Hind.

SHR! B.V. ABDULLA KOYA (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, it is a pleasure to support the present Appropriation Bill, 1976, presented at a time of price stability and national discipline. The Bill has rightly been framed to stimulate production and investment, and has accelerated steady growth in the economy of our country. But it is not out of place to point out here that the considerations shown to the backward areas and backward communities are far from satisfactory. Even though the Deputy Finance Minister claims that she has laid the greatest stress on the completion of ongoing projects like agriculture, irrigation, power, etc., she has not unfortunately given the same importance for the development of backward states, areas and communities which have been neglected for a pretty long time. Sir, States like Kerala, which has accumulated problems like density of population, the largest number of educated unemployed, scarcity of staple food, etc., should have been given some priority in the Budget considering their limited capacity for development on their own, and the scanty attention they have had during the past Five-Year Plans. In Kerala, some of the acute problems like the Calicut aerodrome, the State coir development project, the Guruvayoor-AUeppey railway line, off-shore oil exploitation and develop-

[ShriB. V.Abdulla Koya] ment of Beypore port, are still without any attention from the Central Government to help them. So also, my community, the Muslim community, which' is economically and educationally backward compared to my other sister communities, is not shown the same sympathy and encouragement as shown to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In Kerala, we have a system of reservations for all the backward communities including Ezhavas and Muslims in the educational institutions and Government services. Some such remedial measures by the Centre also are necessary to be taken up, to be followed by other States also.

As for the 20-point programme, all the important patriotic sections and political parties in the country have whole-heartedly supported the measures initiated by our beloved Prime Minister and her Government. But I would say that there is a slackening of discipline in some of the public utility departments like the Posts and Telegraphs, the Telephones and the Railways and also in the Passport Departments now working in Kerala. Our telegrams and letters are very often delayed abnormally even now and the catering service in the Railways is far from satisfactory, if not too expensive and unbearable.

The representation .given to the backward communities in the services is still not upto the mark and no serious attempts are made in this direction.

In the field of family planning, my party and myself wholeheartedly support the Government's policy. But at the same time we are a little perturbed over the over-enthusiasm shown by some of the political workers and officers. I am sorry I cannot support the measures beyond the method of educating and persuading the people. I am against coercive methods. 1 do not forget to acclaim and support the statement of our Prime Minister in this matter that compulsion is not the policy of the Government. Let us follow this spirit.

Another point to be touched upon is the socalled beautification of towns and cities. Un-interested leaders and bureaucr the name of beautifying towns and cities have repeatedly caused untold miseries to the poor people without giving them alternative sites or dwelling units simultaneously.

Lastly, before I conclude, I want to bring to the attention of our Minister the persistent nature of the prices of commodities like toilets, cosmetics and medicines the prices of which have neither fallen nor come to a satisfactory level like the prices of food grains and other articles. Government will have to compare the present prices of such articles to those of pre-emergency period. Even though supplies are satisfactory, Government should take effective measures to bring down their prices also.

In Kerala many of the doubtful economic offenders are kept under custody while notorious offenders are let off. That is the situation we have seen in Kerala and in some other cases. I request the Minister o take this up with the authorities concerned and to see that suitable remedial measures are adopted.

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala) : Mr. Deputy Chairman, I am for the first time on my legs on the floor of this augus House. I am very happy to support the Appropriation Bill presented by the hon. Minister.

Coming as I do from Kerala, 1 feel it my duty to present before this House some of the burning problems of my State. As my friend from the Opposition earlier stated, there are certain urgent problems which have to be tackled immediately and urgently. The first one is the location of the Super Tanker Berth at Cochin. As you may be aware, Cochin has one of the finest natural harbours in India. No less a person than the Prime Minister of India, Shrimati Indira Gandhi, Proclaimed in May 1972 at Cochin that there is no doubt about the sanctioning and commissioning in time of the Super Tanker Berth at Cochin port. Now most disheartening news has come in the press that some Committee has been entrusted with the task of re-examining the necessity desirability or otherwise of sanctioning this very important scheme from the point of view of Kerala and in the interest of the port itself.

Sir, you may be well aware that Cochin is the only port which has on either side two new ports, I mean, the Mangalore Port and the Tuticorin Port. These are very important ports. At the same time, Sir, I may be permitted to point out that Cochin as a port has got the right to continue as well as expand its activities. As a matter of fact, the present position of Cochin

Port is that exports from this port are going down largely because of the fact that no proper attention is paid to it by way of more and better investment on its maintenance and expansion. It might be thought that because of the operation of the oil wells in the Bombay High area, it may not be as necessary as it was found earlier to have the super-tanker berth at Cochin. If the Arabian oil fields can feed the Cochin Refinery which is in urgent need of expansion, as admitted by the Government of India and the Planning Commission, simply because of finding oil in the Bombay High region, should Cochin be denied the opportunity to expand? That is why I say that the sanctioning and commissioning of the super-tanker berth at Cochin at the earliest is one of the most important problems and one of the most important and urgent needs of the State of Kerala and it is not only the urgent and important need of the State of Kerala, but it is alsa the urgent and important need of the whole South India.

Sir, you may kindly permit me to say that I hail for the Cochin Port area ; actually, Sir, I hail from the particular village where this super-tanker berth is to be located. Sir, I do not want to press this point any further. I would earnestly request the Government to. see that the demands of the Cochin Port and the requirements of the State of Kerala are properly attended to and the super-tanker berth, as promised by the Prime Minister which has been already examined and finalised, is commissioned early.

My second point is about the setting up of a Coconut Board which has been recommended by the State Government. Sir. Kerala, as you know, is the land of coconuts and Kera means cocontuts. Probably, Sir, Kerala has near monopoly in this particular agricultural commodity. Therefore, it is no gainsaying the fact that the Kerala State Government has made an appropriate recommendation, a pertinent recommendation to the Government that a Coconut Board should be constituted as a statutory body urgently.

Then, Sir, my third point is about the development of the coir industry. A sum of about seven crores of rupees was promised by the Ministry of Industry a little earlier. But I do not know why that money is not forthcoming though we have waited sufficiently long. I do not know what exactly is going to be the amount if at all it is going to be sanctioned. Sir, this is an industry and coir is a very important fibre produced in India and it is as important as jute if not more. Therefore, it is the urgent duty of the Government of India to see that this industry is allowed to expand since it is a very good foreign-exchage-earning industry. Coir industry is largely a cottage industry which feeds nearly fifteen lakhs of people in the coastal areas of my State. Sir, these fifteen lakhs of workers, the le half-starved workers and under-paid workers and these underemployed workers are not interested in your hair-splitting arguments or recommendations regarding the pattern of assistance or the quantum of assistance that should be made available to the industry for the benefit of Kerala.

My fourth point is the development of handloom. Handloom development is one of the items of the 20-point programme. Therefore, I need not emphasize on it much because according to the 20-point programme the Government is alive to the situation and to the needs of this particulars industry. My only request is that sufficient amount should be set apart for Kerala for the development of handloom.

I shall be failing in my duty if the question of agricultural development and land reforms is not touched. As is well known, land reforms is the basic economic programme. That should have precedence over any other economic programme. There is a pretty old Resolution of the Karachi Congress formulated about 40 years back. We never had a dearth of slogans or programmes or even policy statements. But there was no yearning, there was no intellectual conviction or even emotional conviction to put forth these programmes. Unfortunately, when the Karachi Resolution was passed by the Indian National Congress, this country was not free. But now this country is free. It should now have been given the utmost priority. The implementation of the slogan 'Land to the Tiller' should have been given the first priority. But so far it was only a slogan. But, fortunately, under the enlightened leadership of our Prime Minister, agrarian reforms and land refoms have been placed

[Shri K. K. Madhavan] as the most important items on the 20-point programme. This is a very important programme and it deserves congratulations from all quarters. This programme should be implemented as the first item on the 20-point programme.

I may be permitted to go a little farther and say that I for one believe that land, which includes water also, and the underground riches are the property of the nation or the property of the people at large. This is a fundamental principle of socialist economy. I fail to see why there should be any hesitation to accept this fundamental principle of socialistic philosophy. So I press that this principle should be accepted before long. If you do not accept it today, Sir, tomorrow you will have to accept it under compulsion.

Now, what is the position about land reforms ? Land should belong to the actual cultivator. This principle is accepted. But I see, as my hon. friend who spoke just before me stated, that big industrialists, big bankers and high placed officers have fabulous incomes by way of savings and earnings through non-agricultural operations. 1 raise this question, Sir, whether this privileged section of the community deserves to have the right to keep land which is the means of agricultural production. I question the validity of our laws which define anybody who owns a few bighas of land as landowner or as farmer. I refuse to concede this. Big industrialists, big bankers or high placed officers with non-agricultural, fabulous incomes should be declared as disentitled to keep land. This is a very important problem.

So far as the question of land reforms is concerned, I come from a State, the State of Kerala, which in the matter of land reforms is a poineer. There is a lot of propaganda about the success of land reforms in this part of the country. I agree with this to an extent, only to an extent. The history of land reforms in Kerala goes back to about four decades.

As an improvement on previous legislation by congress Governments the Land Reforms Act was enacted by the United Front Ministry under compulsion from the Congress. But when the stage of implementation came, they deserted office. Shri Shankaran Namboodiripad who was the Chief Minister at that time tendered his resignation under compulsion of the vested interests who were in the Marxist Communist Party. My friends in the opposition have absented and are not here. Otherwise, they would have found it difficult to defend their action. They did not want to implement it. Then it became the duty of the Congress with the other allied political parties which were returned to power, to implement this law with priority. The present Government is implementing this Land Reforms Act. This implementation is going on for the last four years. 1 may be permitted to state that we have touched only half of the programme. The other half remains to be implemented. I do not know at what point of time it will be completed. We talk a lot about legal assistance to the poor. If there is any sphere in which free legal aid to the poor is necessary, it is the sphere of the small tenants and hut dwellers who seek justice at the doors of the land tribunals. As a lawyer, I have had the painful but pleasant experience of defending these unfortunate people I believe that unless land is placed in the hands of the poorer sections of the society who cultivate and want to cultivate land, there is no salvation for this country. Man> of the poor people want to put up small huts. Tenants without record find it very difficult to prove their cases before the Land Tribunals. That is why I suggest that the officers who decide the destinies of hundreds and thousands of poorers sections of people should be tried and trusted people with a sense of welfare and progress of the poor people. *(Time bell rings).* I may be given a few minutes more, Sir. This is the position. Unless the poorer sections of the society are given proper legal aid, it will be very difficult to implement land reforms.

Now, Sir, I come to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes whose case I have to advocate by virtue of my birth. Some of our friends here were stating that assistance should be given on the basis of economic backwardness. I question this. It has become a fashion to borrow socialistic terminology and socialist ideas without looking into the realities

of this great country, culture of this great country and the tradition, history and geography of this great country. The failure of the communist movement is because of this. While the communist movements on other countries have succeeded and have come to occupy seasts of power, it has fallen as under in this country. Why ? Because they do not know this country. They do not understand the people of this country.

When Karl Marx formulated his philo sophy one century and a quarter ago, sitting in the British Museum in London, he did not know, he did not conceive of the social conditions in India. Of course, he has written a few articles on India. I do not hide that. But Karl Marx's phraseology as well as his philosophy and his economic theory formulated without looking into the face of the Indian economy as well as the Indian society and the social order. That is why they have failed. And no less a person than Mahatma Gandhi, the Father of the Nation, took up the responsibility, and the cause of bringing up the Hanjans the downtrodden, the lowest among the *low.* Thanks to the Father of the Nation—Sir, I pay homage to the Father of the Nation— Mahatma Gandhi and the architect of the nation, the late Jawaharta! Nehru. These great leaders of this country served the Harijans and they have taken up their cause and tried to place them on their rightful place. Now, what is the position ? There is some assistance, some sort of educational and financial assistance, and some assistance by way of recruitment and even in promotions being given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That serves to solve only a part of the problem. These measures are meant for undoing the wrongs done to a set of people, a class of people, for centuries and I may say for ages. The wrongs done to these unfortunate people in the course of centuries, in the course of ages, cannot be wiped off overnight. They cannot be wiped off in 25 years. It will take much more time to annihilate these shameful injustices from the face of this country. So, I would plead that more vigorous measures, more liberal measures, have to be adopted for the amelioration of the conditions of this weakest sections of the people— 5—M238RSS/76

the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(Time bell rings.)

Sir, one more point about bonded labour. We are abolishing bonded labour after 25 years of the establishment of the Republic of India. Now, Sir, restoration of tribal lands is one of the points in the 20-point programme. Today, I read in some newspapers that restoration of tribal lands to these unfortunate, poorest sections of people has found utmost resistance and opposition in Maharashtra. If this is the position in an enlightened State like Mah?.-rashtra, I shudder to think what would be the condition in the backward areas. I request the Government to bestow very-very urgent attention to this important problem. Sir, in my own State, resistance to the restoration of tribal land is increasing because of the latest political conditions and pattern of political relationship. I am afraid, Sir, that one important point in the 20-point programme, namely restoration of tribal lands, probably, will be the first casualty in my State in the present set-up unless prevented. I would request that the Government of India should come forward with .a more vigorous policy and give mandatory directives to all States that these erstwhile slaves and tribals should be looked after in a better way. Thank you.

شری سید نظام الدین (جموں و کشمیر) : جناب والا—اس اپروپریشن بل کے سلسلہ میں پچھلے دو دنوں سے آنریبل ممبران کی طرف سے بہت سے مسئلوں کی طرف آنریبل فائننس منسٹر صاحب کی توجہ دلائی گی ہے۔ ہمارا بہت بڑا ملک ہے اور اس کے بہت بڑے مسائل بھی ہیں جن کی نوعیت بھی مختلف ہے ۔ اور ہر ایک مسئلہ کے حل کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ بھی جنم لیتا ہے ہماری عادت صرف ان چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے جو کام نہیں ہوا ہے ہم اگر جائزہ لیں پچھلے ایک سال کا اور غیر

پروگرام کے بارے میں کہ اس پر اس جوش و خروش کے ساتھ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے جس تندھی اور جوش خروش کے ساتھ ابتدائی ایام میں ہو رہا تھا۔ شاید ان کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ اس تندھی سے اس جوش خروش سے وہ بات نہیں چلائی جا رہی ہے لیکن یہ کہنا کہ اس سلسلہ میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے۔ بیس نکاتی پروگرام کے بارے میں ہم دعوہ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہی ایک پروگرام ہے جس کا اعلان ہونے کے بعد عمل درآمد شروع ہوا نہیں تو ہم نے دیکھا اس ملک میں جب ہم کسی پروگرام کا اعلان کرتے تھے اس کے بعد وہ اعلان ایک کاغذی اعلان رہ جاتا تھا عملاً اس پر کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا لیکن اس پروگرام کی یہ خوش قسمتی ہے۔ اس پر فوراً عمل درآمد شروع ہوا۔ کوئی بھی پرسنٹیج ہو۔ کوئی بھی فی صد ہو۔ ۱۰ فی صد ۱۵ فی صد ۴۰ فی صد یہ مختلف ریاستوں میں مختلف فی صد بھی ہو سکتا ہے لیکن اس پروگرام کی ایک خوش قسمتی ہے کہ اس پر اناؤنسمینٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اعلان ہونے کے ساتھ اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا اور ساری ریاستیں جو ہیں اپنی اپنی طاقت کے

[شری سید نظام الدین]

جانب داری سے جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ پچھلے ایک سال کے اندر حکومت نے بہت ہی کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں اور وہ کارہائے نمایاں جن کے بارے میں اگر ہم پچھلے سال سوچنا بھی چاہتے تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک سال کے اندر انفلیشنری ٹینڈ جو ہمارا ہے وہ رک جائے گا اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے پچھلے سال جو قیمتیں بڑھ رہی تھیں اس انداز سے کہ جو رات کو قیمت ہوتی ہے وہ صبح کو قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اس انداز سے قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ تو سارے ملک میں ایک قسم کی نا امیدی اور ایک مایوسی پھیل گئی تھی۔ لیکن حکومت نے ایک مصمم ارادہ کر لیا اور ایک عزم کے ساتھ حکومت نے جو قدم اٹھایا تو وہ تمام مسائل جو تھے ان پر ایک روک سی لگ گئی اور روک بھی اس طرح کی لگ گئی کہ آج جب ہم اس سال کے میزانیہ کی بات کر رہے ہیں۔ اس سال کی میزانیہ پر جب ہم بحث کر رہے ہیں تو ہمارے چاروں طرف ایک خوش گوار ماحول نے جنم لیا ہے اور ایسی اقتصادی حالت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ایک خوش آئیند مستقبل کی طرف پر امید نظریوں سے دیکھ رہے ہیں۔

جناب والا—یہاں ہمارے ایک ممبر صاحب کو شکوہ تھا کہ بیس نکاتی

لحاظ سے یہ کہنا کہ کوئی لینڈ لارڈ ہے صحیح نہیں ہے۔ اس لئے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ریاست میں ۲۰ نکاتی پروگرام کے تحت کسی خاص پہلو کے بارے میں زیادہ زور نہ ہو۔ شاید وہاں وہ مسئلہ اتنی شدت کا نہ ہو جیسے ریاست مہاراشٹر میں ہم گھوم آئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں آج لینڈ لیس جو لوگ ہیں۔ غیر زراعتی لوگ ان کو زمین بھی مل رہی ہے ان کو مکان کے لئے جگہ بھی مل رہی ہے۔یہ ٹھیک ہے کہ جگہ کم مل رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مکان مل رہے ہیں۔ بن رہے ہیں۔ ایک بوڑھا ہمیں ملا۔ میں نے پوچھا ۱۰ فٹ کے کمرہ کیا کروگے جب کہ تمہاری اتنی بڑی فیملی ہے تو اس کا جواب یہ تھا کہ کم سے کم ۸۵ سال کی عمر میں مجھ کو ایک چھت تو مل گئی نیچے رہنے کے لئے۔ اس حد تک وہ خوش تھا کہ کچھ اس کو مل گیا ہے۔ بہر حال یہ بات میں نے یہاں ضمناً کہی قیمتوں کے گراوٹ کے بارے میں۔ مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ جو مینوفیکچرڈ گڈس ہیں۔ مطابق اپنے اپنے فنڈس کے مطابق اپنے اپنے ریسیورسیز کے مطابق اس پر پورا عمل درآمد کر رہی ہیں اور مسائل بھی مختلف ہیں ریاستوں میں۔ ریاستوں میں کہیں لینڈ ٹو دی ٹیلر کا جو پرابلم ہے غیر زراعت پیشوں کو زمین دینے کا جو سوال ہے وہ کہیں زیادہ شدت کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس لئے ان ریاستوں میں شدت سے کام کرنے کی ضرورت پڑے گی جموں اور کشمیر کو یہ خوش قسمتی حاصل رہی ہے کہ سنہ ۱۹۴۷ میں آزادی ملنے کے ساتھ ساتھ ہی وہاں لینڈ ریفارمس ہو گئے اور لینڈ ریفارمس بھی اس قسم کی زمین لینڈ ریفارمس بھی اس قسم کی زمین کی زیادہ سے زیادہ حد جو زمین داروں کے پاس رہ گئی جن کے پاس چار چار پانچ پانچ ہزار کنال تھے ان کے پاس ساڑھے بارہ ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں رہی اور سارے جموں و کشمیر میں اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو کسی شخص کو لینڈ لارڈ کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں پر بھی درمیان میں لوگوں نے زمین خریدنا شروع کر دی اور زمین داروں کی ایک اور کلاس نے جنم لے لیا۔ لیکن اس

بہر حال مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ خالی جو قیمت ہے وہ پروڈکشن کے لئے ضروری نہیں ہے۔ مجھے شک ہوتا ہے اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر زرعی پیشہ لوگوں کو ان کی پیداوار کا پورا ریومنٹری پرائس نہیں ملا جو اس وقت ہم بمپر کروپ دیکھتے ہیں اسے ہاتھ دھونا پڑے گا کبھی وہ کریش کراپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ ابھی جیسا ہمارے دھلپ صاحب کہہ رہے تھے کہ کاٹن کی قیمت بہت کم تھی جب ریل پروڈیوسر اس کو پیدا کرکے بیچتا تھا اس کو کم قیمت ملتا ہے اور جب وہ ہول سیلر کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اس کی قیمت بڑھانی شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریل پروڈیوسر ہوتا ہے اس کو کوئی فایدہ نہیں مل رہا ہے۔

یہ چند باتیں کہنے کے بعد میں اب مین بجٹ کی طرف آتا ہوں اور ایک خاص بات کی طرف ایوان کا دھیان دلانا چاہتا ہوں؛ اس سال کی بجٹ میں جامع منصوبہ دیہاتی ترقی کے لئے رکھا گیا ہے۔ کافی رقم رکھی گئی ہے لیکن جہاں تک

[شری سید نظام‌الدین]

اور کارخانہ دار جو چیزیں بناتے ہیں ان کی قیمتیں اس حد تک نہیں گر گئی ہیں جس حد تک زرعی پیداوار کی چیزوں کی قیمتیں گری ہیں۔ اور زرعی چیزوں کی قیمتیں اس حد تک گر چکی ہیں جس حد تک انہیں نہیں گرنا چاہئے تھا اس کے لئے میں حکومت سے پر زور استدعا کروں گا کہ حکومت کو اس کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہئے۔ اس سال فصل اچھی پیدا ہو گئی ہے اور چودھری صاحب نے جو بتایا کہ فصل کی جو قیمت ہے وہ فکٹر نہیں ہے ریسپونسپیل نہیں ہے پروڈکشن کے لئے - میں مانتا ہوں۔ یہی ایک فیکٹر نہیں ہو سکتا لیکن یہ سب سے بڑا اہم فیکٹر ہے اور سب سے بڑی اہم چیز ہے جو جو شخص پیدا کرتا ہے کہ اس کو اپنی پیداوار کا کتنا ریٹرن ملتا ہے۔ ہم نے بہت دفعہ سوال پوچھا جو مینمم سپورٹ پیرائس فیکس کی جاتی ہے وہ کس چیز کو اندازہ لگا کر فیکس کی جاتی ہے۔ کیا ایگریکلچرس امپوٹس نظر میں رکھ دیا۔ ایگریکلچر پر جو خرچ کرتے ہیں۔ پیداوار کو اگانے کے لئے جو خرچ کیا جاتا ہے کیا اس کا بھی خیال اس سلسلہ میں کیا جاتا ہے۔

اس کے لحاظ سے۔ ان کی جو بیک ورڈ نیس ہے اس کے لحاظ سے انہیں ہل ایریاز قرار دیا ہے۔

اب تک بہت دفعہ کہا گیا ہے کہ جو ہل ایریاز ہیں وہ بیک ورڈ بھی ہیں ان کی مسئلے مختلف بھی ہیں اور شہروں کے جو عام مسئلے ہیں ان کے مسئلوں سے مختلف ہیں —

جیسے ڈینسیٹی آف پاپولیشن بہت کم ہے۔ اس کے باوجود جو رقبہ انہیں حاصل ہے اور جس پر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ڈینسیٹی آف پاپولیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے پاس بہت کافی زمین ہے لیکن کاشت کاری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے پاس بہت کم زمین ہے۔ اس لئے ان کے مسائل مختلف قسم کے مسائل ہیں۔ اور مختلف مسائل سے جب ہم کو ڈیل کرنا ہو تو ہمارا اپروچ بھی مختلف ہونا چاہئے۔ جو اپروچ ایگریکلچر کے لئے یہاں ہے وہ ہل یریاز میں کام نہیں دے گا۔ میری گذارش یہ ہے کہ جو ہل ایریاز ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے—

جناب والا—پچھلے سال ہم نے یہاں ایک ہل ایریاز کی کانفرنس بلائی تھی۔ وہ پہلا نیشنل سیمنار تھا جو پہاڑی علاقوں کے مسائل سے متعلق تھا اس منصوبہ کا تعلق ہے شاید وہ ہماری دیہاتی دنیا کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی ہے کیوں کہ پچھلے ۲۵ یا ۳۰ سال کی آزادی کے بعد جو ہماری ترقی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے کافی ترقی کی ہے۔ ہماری کافی آمدنی بڑھی ہے۔ ہماری پیداوار بڑھ گئی ہے۔ انڈسٹریل اور ایگریکلچر پروڈکشن سب کچھ بڑھ گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب ہم دیہاتوں کی طرف جاتے ہیں جب ہم اپنی نیشنل انکم کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے کسانوں کی حالت کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری نیشنل انکم ہے کہ وہ نیشنل انکم زمین اور آسمان کے بیچ میں کھو گئی ہے اور دیہاتوں میں نہیں ہے۔ شہروں کی طرف جب آتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی ہوئی ہے۔ جو جامع منصوبہ انٹریگیٹیڈ ڈولپمنٹ رورل ایریاز کے لئے پیش کیا گیا ہے اس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہئے۔ میں ایک خاص بات کی طرف جناب کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہم نے کچھ ایریاز ہل ایریاز قرار دیئے اور ہل ایریاز اس لحاظ سے جغرافیائی لحاظ سے جو ان کی ٹوپوگرافی ہے

[شری سید نظام الدین]

اور پہاڑی علاقوں میں جو وسائل چھپے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی تھا۔ ہمیں فخر حاصل ہوا کہ پرائم منسٹر آف انڈیا نے اس کو ایڈریس کیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا——

"I have urged the Planning Commission in the past to give special attention to the problems of hill areas."

"Unless adequate programmes are evolved for the conservation and proper utilisation of the resources of the hill areas, problems would arise not only for those areas, but, problems would crop up which would seriously affect the economics of the plains also."

وہ پلاننگ کمیشن کو اکثر کہتی آئی ہیں کہ جو ہل ایریاز کے مسائل ہیں ان کی طرف خاص توجہ دی جائے۔ جناب والا—۱۹۶۵ میں نیشنل ڈولپمنٹ کونسل کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی انہوں نے سفارش کی تھی۔

"Special measures should be taken to accelerate the process of development in the hill areas."

جو ہمارا مسودہ تھا پنج سالہ منصوبہ کا اس میں بھی پلاننگ کمیشن نے ہدایت دی تھی ریاستوں کو——

"to draw up a separate integrated plan for the hill areas."

۱۹۶۵ میں نیشنل ڈولپمنٹ کونسل نے اس کے بارے میں کہہ دیا جو ڈرافٹ پلان تھا اس میں بھی کہا گیا کہ ہل ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کی طرف خاص توجہ دی جائے۔ ہل ایریاز کے بارے میں یہ بھی کہا گیا۔ پنج سالہ منصوبے کے مسودہ میں——

"The hill areas differ in their resource endowments, problems and potentialities. They should be looked upon as distinct entities and no general purpose programmes or schemes should be thrust upon them."

اگر عام منصوبوں کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ ہل ایریاز کے لوگ بھی ترقی کریں گے تو یہ ناممکن سی بات ہے کیوں کہ ان کے اپنے مسائل ہیں جیسے کہ ایگریکلچر میں وہ اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے جتنے کہ ہارٹی کلچر میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ان کے فارسٹ ڈولپمنٹ کی جو پرابلمس ہیں وہ بھی میدانی علاقوں کے فارسٹ ڈولپمنٹ کی پرابلمس سے ڈیفرنٹ ہیں۔

اس طرح جو ہماری مین انڈسٹری ہے کیٹل ڈولپمنٹ ہے فشریز ہیں وغیرہ یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ ان کی نوعیت مختلف قسم کی نوعیت ہو سکتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہائڈل پاور پٹنشیل ہل ایریاز میں ہے اس کو ڈولپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے ملک کو یہ فائدہ ہوگا کہ ملک کو انرجی سستے داموں میں ملے گی اور ساتھ میں ہل ایریاز کو ڈولپ

کرنے کا آپ کو پورا موقعہ ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی ہے - اور میری جناب والا کی وساطت سے پرزور اپیل ہوگی کہ ان علاقوں کی طرف جن کی نشاندھی پلاننگ کمیشن نے بھی کی ہے ان کی طرف خاص توجہ دی جائے کیوں کہ یہ ہمارے سینسیٹو ایریاز ہیں - اس لئے اس بات کی بہت خاص ضرورت ہے-

†[श्री **सैयद निजामुद्दीन** (जम्मू और काश्मीर) : जनाब वाला--इस एप्रोप्रियेशन बिल के सिलसिले में पिछले दो दिनों से आनरेबल मेम्बरान की तरफ से बहुत से मसलों की तरफ आनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तव्जहा दिलाई गई है। हमारा बहुत बड़ा मुल्क है और इसके बहुत बड़े मसाइल भी हैं । जिनकी नौयीअत भी मुखतलिफ है और हर एक मसला के हल के साथ एक दूसरा मसला भी जन्म लेता है। हमारी आदत सिर्फ उन चीजों की तरफ ध्यान देना है जो काम नहीं हुआ है। हम अगर जायजा लें पिछले एक साल का और गैर-जानिबदारी से जायजा लें तो हम देखेंगे कि पिछले एक साल के अन्दर हुकूमत ने बहुत ही कारहाय नुमाया अन्जाम दिये हैं और वो कारहाय नुमाया जिनके बारे में अगर हम पिछले साल सोचना भी चाहते तो सोच भी नहीं सकते थे कि एक साल के अन्दर इन्फेलशनरी ट्रेन्ड जो हमारा है वो रुक जायेगा और हम सोच भी नहीं सकते थे पिछले साल जो कीमतें बढ़ रही थीं इस अन्दाज से कि जो रात को कीमत होती है वह सुबह को कीमत नहीं होती है। इस अन्दाज से कीमतें बढ़ रही थीं तो सारे मुल्क में एक किस्म की ना-उम्मीदी और एक मायूसी फैल गई थी । लेकिन हुकूमत ने एक मुसम्मम इरादा कर लिया और एक अजम के साथ हकूमत ने जो कदम उठाया तो वो तमाम मसाइल जो थे उन पर एक रोक सी लग गई और रोक भी इस तरह की लग गई कि आज जब हम इस साल के मिजानिया की बात कर रहे हैं इस साल की मिजानिया पर जब हम बहस कर रहे हैं तो हमारे चारों तरफ एक खुशगवार माहोल ने जन्म लिया है और ऐसी इक्तसादी हालत पैदा हो गई है कि हम एक खुश आइन्द मुस्तकबिल की तरफ पुरउमेद नजरों से देख रहे हैं। जनाब वाला, यहां हमारे एक मेम्बर साहब को शिकवा था कि बीस नक्काती प्रोग्राम के बारे में कि इस पर इस जोश खरोश के साथ अमल दरामद नहीं हो रहा है जिस तंददही और जोश खरोश के साथ इब्तदायी अय्याम में हो रहा था। शायद उनकी बात इस हद तक सही है कि उस तंदही से उस जोश व खरोश से वह बात नहीं चलायी जा रही है लेकिन यह कहना कि इस सिलसिले में कोई काम नहीं हो रहा है मैं समझता हूं यह दुरुस्त नहीं है। बीस नम्काती प्रोग्राम के बारे में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यही एक प्रोग्राम है जिसका ऐलान होने के बाद अमल दरामद शुरू हुआ नहीं तो हमने देखा इस मुल्क में जब हम किसी प्रोग्राम का एलाहन करते थे उसके बाद वह ऐलान एक कागजी ऐलान रह जाता था अमलन इस पर कोई काम नहीं किया जाता था लेकिन इस प्रोग्राम की यह खुशकिस्मती है। इस पर फौरन अमल दरामद शुरू हुआ। कोई भी परसेंटेज हो, कोई भी फीसद हो-10 फीसद 15 फीसद 40 फीसदी यह मुखतलिफ रियायतें में मुखतलिफ फीसद भी हो सकता है लेकिन इस प्रोग्राम की एक खुशकिस्मती है कि इस पर एनाउंसमेंट होने के साथ साथ इसके ऐलान होने के साथ इस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया और सा

†[ ] Hindi transliteration.

[श्री सैयद निजामुद्दीन]

रियासतें जो हैं अपनी अपनी ताकत के मुताबिक अपने अपने फण्डस के मुताबिक अपने-अपने रिसोर्सेज़ के मुताबिक इस पर पूरा अमल दरामद कर रही है और मसाइल भी मुखतलिलफ हैं रियासतों में। रियासतों में कहीं लण्ड टू दी टिलर का जो प्रोब्लम है, गैर-जरायत पेशों को जमीन देने का जो सवाल है वो कहीं ज्यादा शिद्दत का मसला हो सकता है। इसलिये उन रियासतों में शिद्दत से काम करने की जरूरत पड़ेगी। जम्मू और काश्मीर को यह खुशकिस्मती हासिल रही है कि 1947 में आजादी मिलने के साथ-साथ ही वहां लैण्ड रिफारमस हो गये और लैण्ड रिफारमस भी इस इस किस्म के कि जमीन की ज्यादा से ज्यादा हद जो जमीदारों के पास रह गई जिनके पास चार चार पांच-पांच हजार कनाल थे उनके पास साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रही। और सारे जम्मू व काश्मीर में अगर इस लिहाज से देखें तो किसी शख्स को लैण्डलार्ड कहना मुनासिब नहीं होगा। यह बात ठीक है कि वहां पर भी दरम्यान में लोगों ने जमीन खरीदना शुरू कर दी और जमीदारों की एक और क्लास ने जन्म ले लिया। लेकिन इस लिहाज से यह कहना कि कोई लैण्डलार्ड है सही नहीं है। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी रियासत में 20 नुकाती प्रोग्राम के तहत किसी खास पहलू के बारे में ज्यादा जोर न हो। शायद वहां वह मसला इतनी शद्दत का न हो जैसे रियासत महाराष्ट्र में हम घूम आये तो वहां मैंने देखा कि वहां आज लैण्ड लेस जो लोग हैं। गैर-जरायती लोग उनको जमीन भी मिल रही है उनको मकान के लिये जगह भी मिल रही है। यह ठीक है कि जगह कम मिल रही है—छोटे-छोटे मकान मिल रहे हैं, बन रहे हैं। एक बूढ़ा हमें मिला—मैंने पूछा तुम 10 फुट के कमरा में क्या करोगे जबकि तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली है तो इसका जवाब यह था कि कम से कम 85 साल की उम्र में मुझको एक छत तो मिल गई नीचे रहने के लिये इस हद तक वह खुश था कि कुछ उसको मिल गया है। बेरहाल यह बात मैंने यहां जमनन कही, कीमतों के गिरावट के बारे में। मुझे इस बात से इतफाक है कि जो मेन्युफेक्चर्ड गुड्स हैं और कारखानादार जो चीजें बताते हैं उनकी कीमतें इस हद तक नहीं गिर गई हैं जिस हद तक जरई पैदावार की चीजों की कीमतें गिरी हैं और जरई चीजों की कीमतें इस हद तक गिर चुकी है जिस हद तक इन्हें नहीं गिरना चाहिए था। इसके लिए मैं हकूमत से पुरजोर इस्तफा करूंगा कि हकूमत को इसके बारे में बहुत मोहताज रहना चाहिए। इस साल फसल अच्छी पैदा हो गई है और चौधरी साहब ने जो बताया कि फसल की जो कीमत है वो फैक्टर नहीं है रेसपोंसिबल नहीं है प्रोडक्शन के लिए। मैं मानता हूं यह एक फैक्टर नहीं हो सकता लेकिन यह सब से बड़ा अहम फैक्टर है। और सबसे बड़ी अहम चीज है जो शख्स पैदा करता है कि उसको अपनी पैदावार का कितना रिटर्न मिलता है। हमने बहुत दफा सवाल पूछा जो मिनिमम स्पोर्ट प्राइस फिक्स की जाती है वो किस चीज को अन्दाजा लगा कर फिक्स की जाती है—क्या एग्रीकल्चर इनपुट्स नजर में रखकर या एग्रीकल्चर पर जो खर्च करते हैं, पैदावार को उगाने के लिये जो खर्च किया जाता है क्या उसका भी सख्याल इस सिलसिले में किया जाता है बेरहाल मुझे इस बात से इत्तफाक नहीं है कि खाली जो कीमत है वह प्रोडक्शन के लिये जरूरी नहीं है। मुझे शक होता है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर जरई पशा लोगों को उनकी पैदावार का पूरा रियूमनरेट्री प्राइस नहीं मिला जो उस वक्त हम बम्पर क्रोप देखते हैं उससे हाथ धोना पड़ेगा। वे केश क्रोप

की तरफ भी जा सकते हैं। अभी जैसा हमारे धुलप साहब कह रहे थे कि काटन की कीमत बहुत कम थी। जब रीयल प्रोड्यूसर इसको पैदा करके बेचता था उसको कम कीमत मिलता है और जब वो होलसेलर के पास आ जाता है तो वो उसकी कीमत बढ़ानी शुरू कर देता है, तो उसका नतीजा यह होता है कि जो रीयल प्रोडयूसर होता है उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है।

ये चन्द बातें कहने के बाद में अब मेन बजट की तरफ आता हूं और एक खास बात की तरफ ऐवान का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस साल के बजट में जामे मनसूबा देहाती तरक्की के लिये रखा गया है, काफी रकम रखी गई है लेकिन जहां तक इस मनसूबा का ताल्लुक है शायद वह हमारी देहाती दुनियां की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है क्योंकि पिछले 25 या 30 साल की आजादी के बाद जो हमारी तरक्की हुई है उस में कोई शक नही है कि हम ने काफी तरक्की की है। हमारी काफी आमदनी बढ़ी है। हमारी पैदावार बढ़ गई है—इण्डस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोड्क्शन सब कुछ बढ़ गया है लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम देहातों की तरफ जाते हैं जब हम अपनी नेशनल इनकम की तरफ देखते हैं और अपने किसानों की हालत की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम जमीन और आसमान के बीच में खो गई है और देहातों में नहीं है। शहरों की तरफ जब आते हैं तो थोड़ा सा हमें पता लगता है कि हमारे मुल्क की तरक्की हुई है जो जामया मनसूबा इज्ण्टीग्रेटिड डैव्लपमेंट रूरल ऐरियाज के लिये पेश किया गया है उसकी तरफ हमें ज्यादा तव्वजो देनी चाहिए। मैं एक खास बात की तरफ जनाब की तव्वजो मबजूल करना चाहता हूं वह यह कि इस मुल्क में हमने कुछ एरियाज हिल एरियाज करार दिये और हिल एरियाज इस लिहाज से जुगराफआई लिहाज से जो उनकी टापोग्राफी है उसके लिहाज से—उनकी जो बैक्वर्डनैस है उसके लिहाज से इन्हें हिल एरियाज करार दिया है। अब तक बहुत दफा कहा गया है कि जो हिल एरियाज हैं वो बैकवर्ड भी हैं। उनके मसले मुखतलिफ भी हैं और शहरों के जो आम मसले हैं उनके मसलों से मुखतलिफ हैं। जैसे डेनसिटी आफ पापुलेशन बहुत कम है इसके बावजूद जो रक्कबा उन्हें हासिल है और जिस पर वे जिन्दा रहना चाहते हैं अगर डेनसिटी आफ पापुलेशन की एतबार से देखा जाये तो उनके पास बहुत काफी जमीन है लेकिन काश्तकारी के लिहाज से देखा जाये तो उनके पास बहुत कम जमीन है। इसलिए उनके मसाइल मुखतलिफ किस्म के मसाइल हैं। और मुखतलिफ मसाइल से जब हम को डील करना हो तो हमारा एप्रोच भी मुखतलिफ होना चाहिये जो एप्रोच एग्रीकल्चर के लिए यहां है वो हिल एरियाज में काम नहीं देगा। मेरी गुजारिश यह है कि जो हिल एरियाज हैं उनके बारे में थोड़ी सी तव्वजो देने की जरूरत है।

जनाब वाला, पिछले साल हमने यहां एक हिल एरियाज की कांन्फ्रेंस बुलाई थी, वह पहला नेशनल सैमिनार था जो पहाड़ी इलाकों के मसायल से मुतल्लिक था और पहाड़ी इलाकों में जो मसाइल छिपे हुये हैं उनके बारे में भी था। हमें फक्र हासिल हुआ कि प्राइम मिनिस्टर आफ इण्डिया ने उसको एड्रेस किया था और उन्होंने फरमाया था—

"I have urged the Planning Commission in the past to give special attention to the problems of hill areas."

और इन्होंने उसके साथ यह भी कहा—

"Unless adequate programmes are evolved for the conservation and proper

[श्री सैयद निज़ामुद्दीन]

utilisation of the resources of the hill areas, problems would arise not only for those areas, but, problems would crop up which would seriously affect the economics of the plnins also".

वो प्लानिंग कमीशन को अक्सर कहती आई हैं कि जो हिल एरियाज के मसाइल हैं उनकी तरफ खास तव्वजो दी जाये। जनाब वाला 1965 में नेशनल डव्ल्पमेंट कोन्सिल की एक कमेटी बनाई गई उन्होंने सिफारिश की थी—

"Special measures should be taken to accelerate the process of development in the hill areas."

जो हमारा मसौदा था पांच साला मनसूबा का उसमें भी प्लानिंग कमीशन ने हिदायत दी थी रियास्तों को—

"to draw up a separate integrated plan for the hill areas".

1965 में नेशनल डव्ल्पमेंट कोंसिल ने इसके बारे में कह दिया जो ड्राफ्ट प्लान था उसमें भी कहा गया कि हिल एरियाज के लोग हैं उनकी तरफ खास तवज्जो दी जायें हिल एरियाज के बारे में यह कहा गया पांच साला मनसूबे के मसौदा में—

"The hill areas differ in their resource endowments, problems and potentialities. They should be looked upon as distinct entities and no general purpose programmes or sehemes should be thrust upon them."

अगर आम मनसूबे के तहत हम समझते हैं कि हिल एरियाज के लोग भी तरक्की करेंगे तो यह नामुमकिन सी बात है क्योंकि उनके अपने मसाइल है जैसे कि एग्रीकल्चर में वो इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते जितने कि हार्टीकल्चर में आगे बढ़ सकते हैं । इसी तरह से इनके फारिस्ट डैवलपमेंट की जो प्राब्लम्स हैं वो भी मैदानी इलाकों के फारेस्ट डवलपमेंट की प्राब्लम्स से डिफरेंट हैं।

इस तरह जो हमारी मेन इण्डस्ट्री है केटिल डेव्लपमेंट है फिशरीज हैं वगैरा ये ऐसे मसायल हैं कि उनकी नौयत मखतलिफ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो हाइडल पावर पोटेंशियल हिल एरियाज में हैं उसको डैव्लप करने की जरूरत है और उससे मुल्क को यह फायदा होगा कि मुल्क को एनर्जी सस्ते दामों में मिलेगी और साथ में हिल एरियाज को डैव्लप करने का आपको पूरा मौका मिलेगा। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। और मेरी जनाब वाला की बसातत से पुरजोर अपील होगी कि इन ईलाकों की तरफ जिनकी निशानदेही प्लानिंग कमीशन ने भी की है उनकी तरफ खास तवज्जो दी जाये क्योंकि ये हमारे सेंसेटिव एरियाज हैं। इसलिए इस बात की बहुत खास जरूरत है।]

श्री सतपाल मित्तल (पंजाब) : डिप्टी चैयरमैन साहब, सब से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप ने मुझे मौका दिया इस सदन में, इस एवान में पहली तकरीर करने का, जिस सदन में कि महबूब प्रधान मंत्री जी की बसातत से मैं पहुंच सका । मैं फाइनेंस मिनिस्टर को बधाई दूंगा कि उन्होंने बजट एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा 37 फीसदी प्लाण्ड डवलपमेंट के लिए रखा है। अगर हम अपने देश के पहले चार प्लानों की तरफ देखें और जो प्लाण्ड डवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर आज तक परसेंटेज मखसूस होता रहा उनको देखें तो मुझे यह बधाई देने में फख्र महसूस होता है । इस मंन्सूबे में फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा परसंटेज प्लाण्ड डवलपमेंट के लिए रखा है। मैं इस के लिए उन्हें बधाई देना चाहूंगा । यही नहीं, उसमें से भी जिन-जिन मदों पर, जिन-जिन बातों पर खास तौर पर तव्ज्जेह देनी चाहिए उन पर ज्यादा परिसेंटेज खर्च करने के लिए इस मद को एक निहायत ही शानदार तरीके से बांटा गया है ।

[The Vice-Chairman (Shri Loknath Misra) in the Chair]

जैसे इरिगेशन है, कृषि है, इंडस्ट्रियल डवलपमेंट और दूसरी चीजें हैं जो कि प्रधान मंत्री जी के बीस प्वाइंट प्रोग्राम में आती हैं, वह चाहे क्रेडिट फैसिलिटीज की बात हो या और दूसरी बातें हों, जिन के बारे में इस सदन में मेरे साथी काफी कुछ कह चुके हैं। इस 37 परसेंट में से भी जो प्रायरिटीज दी गयी हैं वह प्रायरिटीज उन बातों को दी गई हैं जिन में कि हमारे कदम लोगों को सोशल जस्टिस दिलाने की तरफ इंकलाब की तरफ जाने में आगे और तेजी से बढ़ते हैं। जहां मैं इस बात के लिए उनको बधाई दूंगा वहां मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि हमारे स्टेट की कुछ ऐसी प्राबलम्स हैं कि जिन की तरफ तवज्जेह देना जरूरी है। हमारा स्टेट जो कि एक कृषि प्रधान स्टेट है और जिस में हमारे जुगराफिकल एरिया का 86 परसेंट एरिया इरिगेशन के अंदर आता है वह ऐसा सूबा है कि जिसमें किसान के एक हाथ में हल रहता है और दूसरे हाथ में बन्दूक रहती है और वह अपने देश के बार्डर की हिफाजत करता है और उसी बार्डर पर हल चला कर वह देश के खाने के लिए अनाज पैदा करता है। मैं उस सूबे से आता हूं जिस का बेस एग्रीकल्चर बेस है। छोटा किसान, साढ़े सात एकड़ से नीचे का किसान हमारे कृषि क्षेत्र में 60 फीसदी से ज्यादा हैं। हमारे यहां पंजाब में बड़े किसान नहीं हैं, बड़े जमींदार नहीं हैं, छोटे किसान हैं और अगर उनकी तादाद देखी जाए तो उन का परसेंटेज देख कर आपको खुशी होगी और हैरत भी होगी कि 60 फीसदी से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिन की एकरेज होल्डिंग साढ़े सात एकड़ से कम है।

ऐसे प्रदेश से मैं आता हूं जिसमें सारे हालात के बावजूद हिन्दुस्तान के दूसरे स्टेटों के मुकाबले में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हैं। वहां 46 हजार ट्रैक्टर हैं। इसके बावजूद कि बिल्कुल यह कृषि प्रधान देश है जिसमें इंडस्ट्री नाम मात्र के लिए रही है, जिसके साथ सेंट्रल पूल की तरफ से जिस कद्र इंसाफ होना चाहिए, जिस तरह हमारे साथ सलूक होना चाहिए उतना अच्छा सलूक नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी हमारी स्टेट में जहां तक कृषि का सवाल है हमने कृषि की मद में अगर 1951-52 की फिगर्स को लें और 1975-76 से मिलाएं तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हैरत होगी कि करीब करीब साढ़े चार सौ परसेंट, यानी चार गुनी हमने वृद्धि की। जिस वक्त मुल्क तकसीम हुआ था, पंजाब एक घाटे का सूबा था। इसमें इतना भी पैदा नहीं होता था जितनी हमारे पंजाब की रिक्वायरमेंट थी। आज वही पंजाब, हिन्दुस्तान का यह सरहदी सूबा इस कद्र अनाज पैदा करता है कि नेशनल पूल का 60 परसेंट हम पंजाब से देश को देते हैं। यही नहीं, जिस प्रदेश में कभी चावल पैदा नहीं होता था वहां आज हम 22 लाख टन चावल पैदा करते हैं, अपने उत्पादन का 80 परसेंट सेंट्रल पूल में देते हैं क्योंकि पंजाब के लोग कभी शादी या तफरी पर चावल खायें तो खायें, वह चावल नहीं खाते हैं। तो मैं ऐसी स्टेट से आता हूं जिसकी प्राबलम्स और तरह की हैं। यानी छोटे किसान जो कड़कती हुई बरसात में और चिलचिलाती धूप में जमीन का सीना चीर कर अनाज पैदा करता है उसको राहत चाहिए। राहत इस प्रकार की चाहिए कि उसको फर्टिलाइजर, इन-पुट्स और वह तमाम चीजें जो कि कृषि पैदा करने के लिए जरूरी हैं, वह न सिर्फ उतनी मिकदार में चाहिएं बल्कि सस्ती चाहिएं, सब्सिडाइज्ड रेट में चाहिएं। प्रति हैक्टेयर खाद का इस्तेमाल अगर नेशनल एवरेज लिया जाए

[श्री सतपाल मित्तल]

तो 19.9 किलोग्राम है लेकिन पंजाब में 58 परसेंट प्रति हैक्टेयर हमारा किसान धरती में खाद डालता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब जो घाटे का सूबा था, इन चन्द वर्षों में अच्छी और मार्डन टैकनीक से, कृषि मंत्रालय की कोशिशों से यहां तक पहुंचा है। जितनी चीजों की आवश्यकता उसे है उनको पूरा किया जाए तो डिप्टी चेयरमैन साहब, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि पंजाब इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार होगा कि वह सारे देश की आवश्यकता का अनाज पैदा करे ताकि अमरीका से अनाज न मंगाना पड़े और हमारा 400-500 करोड़ रुपया जो हर साल खर्च होता है विदेशी मुद्रा का वह बच सके और हम दूसरे चीजों में उसको लगा सकें । यह हमारा सरमाया है जिसको हम दूसरी चीजों में लगा सकते हैं ।

दूसरे सूबों के साथी मेरी तरफ देख रहे हैं जो शायद इस बारे में मेरे साथ शामिल होना चाहें । मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि खुशी है कि वह शामिल होना चाहते हैं तो हों, लेकिन मैं एक शिकायत इस वक्त करना चाहता हूं कि जिस वक्त क्रैडिट की बात चलती है तो कामर्शियल बैंकों से जितना डिपाजिट हमारे प्रदेश से मिलता है उसका 44 1/2 परसेंट प्लाऊ बैंक हमें करते हैं हमारी इंडस्ट्री को देने के लिए। मुझे खुशी है कि मेरे पड़ौसी सूबे हरियाणा को 72 परसेंट प्लाऊ बैंक करते हैं। एक दो और स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु को 109 परसेंट मिलता है। मुझे खुशी है, मुझे इससे शिकायत नहीं है ।

4 P. M.

लेकिन मुझे शिकायत यह है कि कामर्शियल बैंक्स जो हैं उसमें पंजाब के किसान का, पंजाब के मजदूर का और पंजाब के मेहनतकश का रुपया है और वह उस की इंडस्ट्री के लिए, फाइनेंस के लिए, कृषि के लिए उसका सिर्फ साढ़े 44 परसेंट वापस देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब के साथ किस किस्म का सलूक हो रहा है। मैं निहायत अदब से एक बात कहना चाहता हूं, मुझे पता नहीं इस सदन में भी कोई इस बात को जानता है या नहीं कि सेंट्रल पूल से इंडस्ट्रियल डैवलपमेंट के लिए पंजाब में जो खर्च हुआ है उससे सिर्फ नांगल फर्टीलाइजर की शकल में हमारे प्रदेश में एक प्रोजैक्ट है। इस नांगल प्रोजैक्ट के अलावा सेंटर की तरफ से हमारे पंजाब में और कोई इन्डस्ट्री नहीं है। कोई न तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है और न ही कोई मिडियम स्केल इंडस्ट्री है। चौथे प्लान तक इस क्षेत्र में 5500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे उसमें से पंजाब के इस प्रोजैक्ट पर सिर्फ 32 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि .06 परसेंट ही हमारे यहां इस प्रोजैक्ट पर खर्च हुआ है।

पांच सलाना मंसूबे में भटिण्डा फर्टीलाइजर प्लाण्ट की बात भी है और इसके लिए 130 करोड़ रुपए निकाल कर दिए हैं। इस बात के लिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब का शुक्रिया करना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं यह जरूर पूछना चाहूंगा कि जब के पंजाब में कोई आयल रिफाइनरी नहीं लग सकती, पंजाब में कोई स्टील प्लांट नही लग सकता क्योंकि उसके लिए उसके नजदीक रा-मैटीरियल और दूसरे सोर्सेज चाहिएं तब क्या पंजाब में कोई इंजीनियरिंग प्रोजैक्ट नहीं लग सकता, क्या पंजाब में एग्रो बैस्ड प्रोजैक्ट नहीं लग सकता और क्या पंजाब में दूसरे लार्ज स्केल के या मिडियम स्केल के उद्योग नहीं लग सकते हम आज जो देखते हैं कि पंजाब में छोटे उद्योग पनप रहे हैं तो वह पनप रहे हैं

पंजाब के उस जवां हिम्मत कारीगर के बलबूते पर जिसका साथ उसके छोटे उद्योग में उनकी मां-बहन और बेटी भी देती है । इसलिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर से अर्ज करना चाहूंगा कि उसे नेशनल डैवलपमेंट कौंसिल की 1965 की रिपोर्ट मद्दे नजर रखनी चाहिए जिसमें कहा गया था कि जहां तक इंडस्ट्रियल डैवलपमेंट के विकास का सवाल है सारे देश में इसके लिए बेलेंस रखा जाए। वह बैलेंस नहीं रखा गया है । टोटली इंम्बैलेंस है । इस इम्बैलेंस को बैलेंस में लाने के लिए आप को जल्दी से जल्दी कार्रवाही करनी चाहिए।

जहां मैंने यह बात कही है वहां मैं यह जरूर कहूंगा कि हमारे ओपोजीशन के भाई यहां इस वक्त बहुत कम बैठे हैं। उन्होंने बहुत सी बातें कहीं हैं। उन्होंने 20 पाइन्ट प्रोग्राम के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, इमरजेंसी के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि पहली बार हिन्दुस्तान के लोगों को इस बात का विश्वास हुआ है कि 29 साल में कानून और संविधान के जरिए भी क्रांति और इन्कलाब आ सकता है। पहली बार उन्होंने इस बात को देखा है कि कानून के द्वारा बांउण्डेड लेबर को हटाया जा सकता है, आजाद किया जा सकता है इस महान देश में 29 साल की आजादी के बाद। पहली बार उनको यकीन हुआ है कि जरूरी नहीं है कि किसी देश में इन्कलाब और क्रांति लाने के लिए खून की होली खेली जाए । उनको इस बात का यकीन हो गया है कि संविधान और कांस्टीट्यूशनल तरीके से भी इन्कलाब लाया जा सकता है। पहली बार हिन्दुस्तान के लोगों को महसूस हुआ है कि अगर कोई प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी महान नेता यह ठान ले कि उसे, इस देश के विकास के लिए, इस देश की उन्नति के लिए, छोटे लोगों को ऊंचा उठाने के लिए संकल्प करना है तो इस देश में इतनी ताकत है कि वह अपने आप ही ऊपर उठ सकता है । 20 पाइण्ट प्रोग्राम हमारा नेशनल चार्टर है। हमारे हिन्दुस्तान के गरीब आदमी को उसकी बैकवर्डनैस से निकालने का यही एक प्रोग्राम है जिससे हम उनको ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि उसको कामयाबी के पथ पर डाला जाए। 20 पाइण्ट प्रोग्राम के इम्पलीमेंटेशन के लिए यह जरूरी है कि चाहे मंत्रालय हों या अन्य कोई सरकारी विभाग हो, हमें इसको सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें वाच डाग कमेटियां बनानी चाहिएं। इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमें लोगों को इन्वाल्व करना होगा और ऐसे लोगों को इन-वाल्व करना होगा जो कामिटेड हों।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बावजूद कि हमारे मुल्क में इस नेशनल इमरजेंसी के दौरान पोलिटिकल और इकोनौमिक क्षेत्र में बहुत डिसिप्लिन आया है, इसके बावजूद बहुत से क्षेत्रों में सुधार हुआ है, लेकिन इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि हमारी ब्यूरोक्रेसी आज भी कामिटेड नहीं है और देश में जब तक कामिटेड आदमी न हों, कामिटेड सर्विस न हो, तब तक ऐसे किसी भी प्रोग्राम को ठीक प्रकार से अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जहां तक 20 पाइन्ट प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, इसके लिए जरूरी है कि हर स्तर पर रिव्यूइंग कमेटीज बनाई जाय और उनमें लोगों को इनवाल्व किया जाय ताकि वे इस बात को अच्छी तरह से देख सकें कि

[श्री सतपाल मित्तल]

हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी मशीनरी है वह किसी किस्म की गड़बड़ी न कर सके। मैं समझता हूं कि जब तक इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम अच्छा होता है, लेकिन वह कागज पर ही रह जाता है। रूरल एरियाज में जिस वीकर सैक्शन को और मजदूरों को जमीन दी गई है, उसमें हमें यह देखना होगा कि उन लोगों को इस जमीन का फिजिकल पजैशन मिल गया या नहीं। इस बारे में देश के मुखतलिफ इलाकों से कई बार शिकायतें आती हैं और हम यह भी देखते हैं कि कई बार फीगर्स कोट कर दी जाती हैं जो कि गलत होती हैं। मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस बात की रिपोर्ट आनी चाहिए कि जिन लोगों को जमीन दी गई है उनको उसका फिजिकल पजैशन मिल गया है या नहीं। सिर्फ कागजी कार्यवाही से काम नहीं चलेगा। अगर आप किसी गरीब आदमी को जमीन दे देते हैं, लेकिन उसको अच्छे बीज, नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, बैल नहीं देते हैं, इनपुट्स नहीं देते हैं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेन्टशन में लोगों को इनवोल्व किया जाए। जब इस देश के अन्दर आजादी का का आन्दोलन चला था तो उस जमाने से महात्मा गांधी जी ने और पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने हमें एक रास्ता दिखाया है। हमें उस रास्ते पर चलना होगा। इसलिए नम्रता से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर लेवल पर वाचडौग कमेटी बनाई जाए। जो कानून हमारे रास्ते रोकते हैं उनको हटाया जाए। कोई भी संविधान लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है न कि लोग किसी संविधान के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए जो कानून हमारे प्रोग्रामों के इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में आते हैं उनको सुधारा जाना चाहिए। आज हमारे देश में जिन लोगों को सहायता की जरूरत है, जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है, उनको यह मदद पहुंचाई जानी चाहिए, आज रूरल ऐरियाज के अन्दर जो खेतिहर मजदूर हैं या जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि कोई भी कानून इंसान की भलाई के लिए बनाया जाता है न कि इंसान कानून के लिए बनाया जाता है। इसलिए मैं वैलकम करता हूं यह जो कमेटी बनाई गई है इसको, जिस कमेटी रिपोर्ट का सारा देश इंतजार कर रहा है। मैं यह कहूंगा, हमारा संविधान बहुत अच्छा संविधान है, बहुत सुन्दर संविधान है, लेकिन उसमें कुछ एसी खामियां हैं जिन को बदलना होगा या हमको उन चीजों को बदलना होगा जो चीजें कि हमारा रास्ता रोके खड़ी हैं। मैं अदब से कहता हूं, फण्डामेंटल राइट के मामले में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 बेंच बनायी थी, जिन दोनों बेंचों ने--चीफ जस्टिस उसके चेयरमैन थे, प्रधान थे--फैसला किया कि फण्डामेंटल राइट को भी बदलने का हक पार्लियामेंट को है, वह पार्लियामेंट जो लोगों की चुनी है, वह पार्लियामेंट जो लोगों की प्रतिनिधि है; वह संविधान को भी बदल सकती है। लेकिन ऐसे हालात इस देश में पैदा किए गए कुछ पार्टियों की तरफ से जो नहीं चाहते थे कि यह देश अपने पाँव पर खड़ा हो, यह देश अपना फैसला खुद कर ले, जो नहीं चाहते थे कि इक्तसादी तरक्की के रास्ते पर सारा हिन्दुस्तान गामजन रहे, जो नहीं चाहते थे कि हिन्दुस्तान में सियासी मज-

बूती नहीं आए, जो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान एशिया में सिर उठा कर चले—उन्होंने ऐसे सियासी हालात पैदा किए जिनको हम कह सकते हैं अफरा-तफरी के हालात थे और ऐसे ही हालात का सहारा लेकर कुछ जुडीशरी ने ऐसी बातें कीं जिसमें ऐसा लगा कि अमीर और जो बड़े सरमायादार, बड़े जागीरदार थे, उनकी खातिर वे कानून की आड़ लेकर खड़े हो गए, और वह गरीब की हिफाजत के लिए नहीं खड़े हुए। इसलिए मैं अदब के साथ और पूर जोर से कहना चाहूंगा . . .

DR. RAMKRIPAL SINHA : On a point of order. Can the hon. Member criticise the judiciary in this way ?

SHRI SAT PAUL MITTAL : I am within my rights to do so.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKA NATH MISRA) : Kindly wind up. You have taken too much time.

SHRI SAT PAUL MITTAL : I was saying that 1 am within my rights to do that AN HON. MEMBER : You are not criticising.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOK-NATH MISRA) : You are not criticising a particular Judge.

श्री सतपाल मित्तल : जो बात आनरेबल मैम्बर कह रहे हैं उससे मैं इत्तिफाक नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि जुडीशरी को क्रिट्रीसाइज करने की बात नहीं है, एक सिस्टम को क्रिटिसाइज करने की बात है, एक ऐसे अनासिर को क्रिटिसाइज करने की बात है जो अनासिर पोलीटिकल मैदान में और हर मैदान में गैंग अप करके हिन्दुस्तान की तरक्की के रास्ते में खड़ा है। इसलिए मैं पूरे जोर से यह बात कहना चाहता हूं कि आज सारा मुल्क इस बात का इन्तजार कर रहा है कि इस कानून को, संविधान को, किस तरीके से बदला जा रहा है बदला जाएगा, जिसकी तरफ सारे हिन्दुस्तान की निगाह लगी हुई है और मैं समझता हूं यह जो महान सदन है, पार्लियामैंट इसकी तरफ हिन्दुस्तान के लोग देख रहे हैं क्योंकि यही पार्लियामेंट है जिसने संविधान को बनाया था और जब-जब लोगों का तकाजा होगा, हम उन तकाजों के मुताबिक संविधान को बदलेंगे। हिन्दुस्तान के लोग सावरेन हैं, उनके हाथ में पूरी शक्ति है, वे अपने नुमाइन्दे बना कर यहां भेजते हैं जो देश की किस्मत का फैसला करते हैं। तो हमारे देश के लोगों की निगाह हम पर लगी हुई है, वे हमसे तवक्को करते हैं हम ऐसे काम करेंगे जिससे हमारे देश के विकास की गाड़ी जल्दी से जल्दी मंजिल तक पहुंचेगी क्योंकि उन्होंने 29 साल इस देश में सब्र किया है, उन्होंने देखा है हमारी करनी और कथनी में अब फर्क होने वाला नही है। हमारे देश की प्रधान मंत्री और संसार की बड़ी नेता प्रधानमंत्री इन्कलाब का परचम लेकर आगे चली है और 20 –सूत्री कार्यक्रम एक ऐसा फरमान है जिसको लेकर हम उस मंजिल तक पहुंचने वाले हैं।

मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस बात का मौका बख्शा कि मैं अपने ख़यालात आपके सामने पेश कर सकूं। जय हिंद।

SHRI F. M. KHAN (Karnataka) : Sir, I welcome this Appropriation Bill and, while welcoming it, I would like to make a few points.

First of all, Sir, some of our Opposition leaders have been criticising the 20-point programme which is totally wrong. I say this because inflation has taken place in the whole world, but not in India, and this has to be highlighted and it has to be highlighted not only in India, but also outside India. It is only the 20-point programme which has stopped the inflation and I think very Indian should be proud of it and this should be highlighted to a very large extent.

[Shri F. M. Khan]

Then, Sir, I would like to touch upon the subject of the MISA. Sir, the MISA has been misused by letting off the black-marketeers who were arrested earlier. I do not know when they were arrested and how they would be let off after a certain period. I would also like to mention here that the blackmarketing and hoarding activities have started again of late.

Then, coming to the question of the compulsory retirement of officers, I would like to say that the corrupt officers have Dot been retired. There are many corrupt officers who have been left out. But some honest officers who have not connived with their superiors have been retired....

DR. RAMKRIPAL SINHA : In which State ?

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY : Please do not interrupt him; he is making his maiden speech.

DR. RAMKRIPAL SINHA : I am not stopping him. I only wanted to know in which State this has happened.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY : In Karnataka.

SHRI F.M. KHAN : Sir, in this connection, I would like to suggest that some non-official body should be set up which should be made to screen the corrupt officers.

Coming to the question of family planning, I would like to say that last year, in Bihar and Rajasthan, even though the entire money was spent, the results obtained are very poor. Since the results are poor, I would suggest that some inquiries should be made against the concerned officials who were responsible for the implementation of the programme and necessary action should be taken against them. This should be taken note of seriously because money from the public ex-chequer has been spent and the net result has not been good at all.

Regarding the question of fixing a ceiling on urban property, I would say that the issue seems to have been side-tracked a tittle and big buildings are coming up in small areas. When the other sections of the society have been subjected to certain restrictions, the holders of urban property should also be dealt with in the same way since the thinking of the entire country is running on these lines.

Then, Sir, while welcoming the reduction in taxes, I would plead for stricted lcollection of taxes. There is a lot of black money is still with the people and with the little knowledge I have and from the little study that I have made, Sir, I have come to certain conclusions and I feel that there are some drawbacks in the scheme for the disclosure of black money. There is black money of more than ten thousand crores of rupees still with the people. The reason why some people are not prepared to disclose their income is that while the Income tax people would take necessary action, the other authorities who are there to take fo'* low-up action like the Sales-Tax or the Excise or the Customs or the Export-Import authorities do not take prompt action. Now, if the Government is determined to get the black money out, I feel that some chance should be given to these people now so that the money is out. Otherwise, when the emergency is lifted some time later, the black money will come again and play its role and a lot of obstacles would be created in the development of our economy and the black money will flourish as a parallel economy in our country.

Then, Sir, a lot of emphasis iias been put on the question of irrigation and power in the last budget and there are some programmes as far as power is concerned. There are some States which have surplus power and this surplus power could be given to those States which have power shortage. For instance, in Karnataka, there is power shortage to the extent of 33 per cent. But there is extra power in Orissa and Kerala and this extra power could be channelised and diverted to Karnataka instead of being wasted in those States.

As far as my knowledge goes, there is some power which can be spared and this could be utilized wherever shortages are there. A lot of money has been spent or irrigation and power. Food production has gone up. But the marketing has not been thought of by the Government. The prices are now falling even below the levy prices. Until and unless the Government takes it seriously, storage will also spoil a lot of food because the farmers do not have scientific storages. If we further allow them to keep-it they are bound to go and sell their

produce to the middleman at a lesser rate which, again, will be sold at a higher rate in the later stages.

Then, I come to another very important point : the implementation of the programme. Whenever a law is voilaled, pubic is also prosecuted. But one section, that is, the officers who arc the main people to implement, is not touched. The accountability of .the officers is not there. If the policies and programmes which are thought of are not implemented, action should also be taken against them. At present the maximum punishment is transfer from one department to another department and they have the assurance that they are there for 30 years whereas the Members are elected for five years. Therefore, I feel that the accountability should be there, as far as officers are concerned.

Then, in the rural areas, farmer cannot afford to go to the headquarters to fight out petty cases. So I feel that mobile courts lor dealing with petty cases in villages would do a lot of good to the poor people. This would save a lot of time of the poor people . Once litigation is there, it takes a very long is there, it takes a very long time. So, I think, mobile courts should be there. For instance, we have land tribunals formed by non-official bodies as well as official bodies wherein 50-60 cases have been decided in a day. Likewise, mobile courts with some amendments would help the poor people in the rural areas.

Then, I come to rural indebtedness. It is good that it has been taken up as one of the items on the programme. But it has not reached all parts. Much more propaganda work has to be done. Some poor people are not in a position to borrow money from banks or any other agency. There are a lot of poor people who borrow by keeping their utensils or clothes-say ten or fifteen or twenty rupees, which would be adjusted. Here, the Government should think of assisting them through banks or something, otherwise a new class of money lenders will start coming up because there are a lot of difficulties faced by the poor sections of the people.

Then, there is another programme which has been chalked out in this country for so many years. According to the statistics collected by the Government, I do not think there would be any space left for a tree to

be planted. Unfortunately, it has become a total failure. So, 1 feel, tree planting should be taken up. It should be given to the younger people. It has already been taken up as one of the projects under the able leadership of Shri Sanjay Gandhi. This project should be entrusted to the Youth Congress, so that tree-planting would be taken up throughout the country. If the younger people are involved, it is going to be a successful project.

Regarding adult education also, I can say that they have been taking it up very seriously. Now that the Government has already laid down a policy about it, I feel thai it should be channelised through this source.

Sir, I thank you for having given me this opportunity.

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों की अत्यन्त आभारी हूं । शायद 24 या 25 की संख्या में कल आज तक उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं और अनेक सुझाव उन्होंने दिये हैं । और मेरे लिए संभव नहीं है कि हर सुझाव के लिये मैं यहां उत्तर दे सकू, पर इतना आश्वासन मैं आप के माध्यम से अवश्य देना चाहूंगी कि जितने सुझाव हैं और वह जिन जिन मंत्रालयों से संबंधित हैं उन पर अच्छी तरह से, गंभीरता पूर्वक विचार जरूर किया जायगा और समय आने पर, सारी चीजों में अच्छी तरह से उन को देख कर आवश्यक कार्यवाही की जायगी

मान्यवर, दो दिन से अपने माननी सदस्यों के भाषण सुनते सुनते मन में सा देश की एक झांकी अपने सामने आयी है औ सब का निचोड़ सारांश एक रहा कि गरीब की कराह देश में है, देश में असमानता है औ अपनी पुरानी संस्कृति को सामने रखते ह हमारे भविष्य के जो संस्कार हों उन किस तरह से एक सामंजस्य लाया जा हमारे नवयुवकों की आकांक्षाओं के अनुस अपने देश को हम किस तरह से आगे ले सकें और साथ ही साथ अपने सीमित साध के द्वारा अपने विशाल देश को किस तरह

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

प्रगति के पथ पर शीघ्र से शीघ्र ले जा सकें। इस की एक आकांक्षा सभी के दिलों में है। अभी कल हमारे चन्द्रमणि भाई ने बताया कि आखिर हम चाहते क्या हैं क्या करना चाहते हैं और वह चीज मेरे दिल में बैठ गयी कि हम एक इंसान बनना चाहते हैं। इंसान तो हमेशा से मिट्टी का होता आया है। वह हाड़ का बना हुआ है, पर आज का इंसान कुछ दूसरी तरह का है। पिछला इतिहास हम देखें, विशेष कर भारत के इंसान में एक विशेषता है कि जो हिंसा में विश्वास नहीं करता, अपने पुराने चार, पांच हजार साल पुराने इतिहास और सभ्यता पर हम दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि अपनी सारी पुरानी चीजों को लेकर शान्ति के पथ पर चल कर वह एक ऐसी सामाजिक क्रान्ति इस देश में लाया और संसार में भी ऐसी क्रान्ति आयी, जिस में हमारे वज्ञानिकों ने एटामिक ऐज में प्रवेश किया और संसार के देश देश का फासला दूर हो गया, और इस नयी हवा में हमारे देश का इंसान भी आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन गरीबी के होते हुए वह कैसे अपने को आगे बढ़ा सकता है और अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति भी रख सकता है कैसे हवाई किले बना कर उड़ सकता है। वह पंछी की तरह पिंजड़े में बंद है। वह धरती पर भी है और ऊंचे आकाश में भी भ्रमण करना चाहता है। यह सारी चीजें हमारे सामने आयीं। हमारे साथी जो थे, उन के मन में जो कष्ट है, जो आकांक्षा है और अपने सामाजिक ढांचे के अंतर्गत एक लोकतांत्रिक पद्धति को स्वीकार करते हुए किस तरह से हम इन तमाम चीजों को कर सकते हैं, कैसे अपने देश को आगे ले जा सकते ह इसके लिए हर एक माननीय सदस्य के दिल में जो चोट थी, जो कराह थी, जो खालिश थी उस के पीछे मैं जानती हूं कि क्या भावना है। ़मारा जो एप्रोप्रियेशन बिल आया है उस ़ लिये उन्होंने अपना समर्थन दिया है। और उन के जितने विचार हैं वे हम को एक ही राह में ले जा रहे हैं। अपने सीमित साधनों के अनुसार जिस की प्राथमिकता देनी है उसे वह प्राथमिकता देते हुए हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। मान्यवर, अगर संसार का इतिहास देखा जाय, जिस के हम एक अंश हैं तो आप को पता चलेगा कि भारत ने पिछले दो, चार सालों में जो कार्य किया है वह स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने के योग्य है। मैं आप के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि पिछले साल भी हमारा बजट आया था। वर्षा कम हुई थी और अंधकारमय वर्ष हमारे सामने था। हमारी नैया मंझधार में आ गयी थी। चारों तरफ से ऊंची तरंगों में, समुद्र में हमारी नाव कभी कभी इधर टास खाती थी, कभी उधर टास खाती थी। और ऐसे समय में जब कि सारे योरप की इकोनामी डोलड्रम्स में थी, उन की करेंसी टाटर कर रही थी, उन के यहां मंहगाई बढ़ती चली जा रही थी, 32 प्रतिशत महंगाई हमारे यहां भी बढ़ गयी थी और वर्षा न होने के कारण कृषि का उत्पादन कम हो गया था, हमारे कच्चे माल का उत्पादन भी गिर गया था और औद्योगिक अशान्ति फैल रही थी, बहुत से लोगों ने नाजायज लाभ उठाने के लिये चीजों को समेट कर रखना शुरू कर दिया था। दाम बढ़ा दिये गये और एक आर्टि-फिशियल स्कैयरसिटी का वातावरण देश में छाया हुआ था। ऐसे वक्त पर एक ऐसी नेतृत्व ने सारी चीज संभाली न होती तो हो सकता था कि हमारी नैया भंवर में पड़ कर समुद्र में फंस गई होती और भारत का प्रकाश लुप्त हो गया होता और आज भारत हिम्मत के साथ इस तरह खड़ा नहीं हो सकता था।

जैसे पंडित जी ने एक बार कहा था—

Success often comes to those who dare and it seldom goes to the timid.

हिम्मत से, सही नेतृत्व ने जनता के विश्वास पर एक कदम उठाया और भारत की जनता ने

एक होकर, चाहे वह किसान हो उसने अपने खेत पर, चाहे फैक्टरी में काम करने वाला आदमी हो, चाहे सरहद पर हमारे सेनानी हों, सबने जगह जगह देश के प्रहरी बनकर प्रधान मंत्री को अपना सहयोग देकर देश में अच्छा काम किया है। जो लोग सारी इकानामी को, लोकतांत्रिक ढांचे को तहसनहस करना चाहते थे, उन्होंने यही नहीं कि ऊपर से तरह तरह के षडयंत्र रचे, अन्दर से बड़े बड़े डाइनेमाइट करने की भी कोशिश की ताकि लोगों की जान जाये, माल जाये और देश का नक्शा बदल जाए, आज उन लोगों की चीजें कामयाब नहीं हुई और सारे देश में जो एक नक्शा देखा सारे संसार ने देखा कि भारत एक अनोखा देश बन गया है। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को सराहा है। यह देश की प्रधान मंत्री, देश के हर एक व्यक्ति चाहे वह महिला हो, वर्कर हो, नौजवान हो सबके कारण ही आज देश में एक नई चीज उत्पन्न हुई है।

आपको याद होगा जब कतारों में बन बन कर हमारी महिलायें जाती थीं राशन की दुकानों पर और उनको लौटा दिया जाता था यह कहकर कि नहीं है, दूसरे दिन आओ। दूसरे दिन लाइन लगाकर जो कुछ सामान मिला तो उसमें क्या क्या मिलता था, बीनने में क्या चीज हाथ में आती थी और क्या चीज हाथ में दी जाती थी। उसके बाद जो तोला जाता था वह तोलकर ठीक नहीं दिया जाता था। बड़े बड़े घरों को वह चीजें पहुंच जाती थीं। पहुंचाने के तरीके हैं, स्वीकार करने के भी तरीके हैं। कभी कभी तो बाल बच्चों को अपनी शिक्षा छोड़कर राशन लेने जाना पड़ता था। एक जमाना था कि लोग मन हुआ तो काम पर गये, मन नहीं हुआ तो काम नहीं करते थे। जिस समय चाहा आफिस में आ जाते थे। वह दिन भी थे जब हमारे विद्यार्थियों को गुमराह करके गलत रास्ते दिखाकर, भड़का भड़काकर शिक्षा से हटाया गया। आज मुझे खुशी है कि सारी चीजें फिर, जैसे शीतल मन्द सुगन्ध पवन के बीच में आकर एक नया रास्ता हमारे सामने आया है, और अपनी अपनी जगह पर बैठकर एक सच्ची, बढ़िया इमारत देश की बन रही है जहां हर एक चीज है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल एक इमारत नहीं, उसके पीछे एक ख्वाब है, उसके पीछे एक सपना है, उसके साथ साथ हर एक का सपना है, सब अपनी अपनी जगह पर बैठा हुआ है। आज भारत का नक्शा जो बन रहा है वह एक नया नक्शा है। हमारे पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेज ने सारी चीजें आज दिखा दी हैं जहां 5 हजार करोड़ रुपये लग गये। यह जरूर है कि उन्होंने काम देर में शुरू किया है लेकिन इतना मजबूत इंफ्रा-स्ट्रक्चर बना है हमारे देश में कि सारे लोग मान गये कि भारत में एक बहुत बड़ी चीज हो गई। हमारे पब्लिक सैक्टर इंटरप्राईजेज का 15 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है और मुझे आशा है कि इसको वह और आगे बढ़ायेंगे। जो एक मनोबल गिरा था, गिराया गया था और मनोबल गिराने के लिए तरह तरह के षडयंत्र देश में और अन्य जगह रचे गये उसके लिए हर तरह से प्रयास किया गया था, आज हर चीज अपनी जगह आ गई और गंगा के जल की तरह साफ होकर वह हमारे सामने निर्मल हो कर आ गई है।

आज देश में एक नया वातावरण आया है और वह वातावरण ऐसा आया है कि लोग देखते हैं तो हैरत होती है। मैं जानती हूं कि सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है। मैं थोड़े से आंकड़े आपके समक्ष रखूंगी। सितम्बर 1974 में होल-सैल प्राइस इंडेक्स 335 तक पहुंच गया था, मैं इस समय नहीं कह सकती कि कितना घटा, लेकिन सबको मालूम है चीजों के भाव गिरने शुरू हो गये। आपने देखा कि हमारे देश की नेशनल इन्कम 0.2 परसेन्ट हो गई थी, भारतीय जनता की मेहनत से, इन्दिरा जी के सही नेतृत्व से और कांग्रेस की जो नीति है जिसके आधार पर सदैव चलते आए हैं जनता का विश्वास प्राप्त करके आज

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

5.5 परसेन्ट तक पहुंच गई है । कृषि का प्रोडेक्शन जो 74-75 में घट गया था और 3.1 कम हो गया था आज हमारे खेतिहर किसानों की मेहनत से और गवर्नमेन्ट की स्ट्रेटेजी के कारण बढ़ा इन्द्र भी मुस्कराये । इन्द्र भी मुस्कराये और इन्दिरा जी ने भी संभाला । दोनों ने मिलकर काम किया और 8 परसैन्ट हमारी कृषि में उत्पादन बढ़ा । आज जो आशा की जाती है कि 118 मिलियन टन तक हम पहुंच जाएंगे, वह आशा पूरी हो जाएगी । इसी तरह से इंडस्ट्रीयल प्रोडेक्शन जो घट कर 2.5 हो गया था अब वह बढ़ कर 4.5 हो गया है । हमारे श्रमिक जानते हैं कि देश में मेहनत से और पसीने की एक-एक बूंद को मोती बना कर देश को बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं । सबसे बड़ी चीज यह है कि पिछले वर्ष जब हमारा वर्ल्ड ट्रेड 6 परसेन्ट घटा था तब भारत का 7 परसेन्ट बढ़ा है । इस बढ़ौतरी से स्पष्ट संकेत मिलता है कि किस तरह से हमारे देश में उन्नति हुई है ।

तेल के बारे में भी आशा की जाती है कि 1980-81 में 20 मिलियन टन क्रूड हो जाएगा जब कि अब 8 मिलियन टन है । हम देख रहे हैं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है या कोई नई जादू की छड़ी हिला दी हो या कोई मंत्र पढ़ दिया हो जिससे दिशा बदल गई हो । इस वक्त भी जब वही लोग हैं, वही इन्सान हैं और वही सारी चीजें हैं तो क्या कारण है कि लोग वक्त से अपने आफिसों में पहुंचने लगे हैं, बच्चे स्कूल टाइम पर पहुंचने लगे हैं, ओवर-टाइम कम हो गया है और देश का उत्पादन बढ़ गया है । हमारे खेतों खलिहानों में, कारखानों में काम शुरू होने लगा है और सारा वातावरण बदल गया है ? मैं केवल यही समझती हूं कि इसके लिये देश में आत्म-विश्वास आया है । देश में जो डायनामिक पालिसी रही है, हमारी प्रोगोमैटिक पालिसी रही है उसी का यह परिणाम रहा है । कोई एक रात में परिणाम नहीं निकल आते हैं । जो हमारा डायनामिक अप्रोच रहा है उसी के कारण ये सब चीजें बदली हैं । इसी के कारण अनुशासन पर्व के रूप में एक नई फिजा आई है । हमारे कच्चे माल की उपलब्धि बढ़ गई है, अब विद्युत की भी कहीं ज्यादा उपलब्धि बढ़ गई है । खाद्यान्न और दूसरी चीजों में भी हमने उन्नति की है ।

हमारी जो एक मंशा है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं वह है सोशल जस्टिस । गरीब और अमीर के बीच जो बड़ी खाई है उसको जल्दी से जल्दी दूर करना, क्योंकि आज भी वह उतनी ही है जितनी पहले थी ।

इसके अलावा सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे बीच में यह है कि भारत की आबादी सारे संसार की आबादी की 7 परसैन्ट है । भारत में केवल ढ़ाई परसैन्ट जमीन है सारे संसार की । हमारी पर-कैपिटा इन्कम केवल ड़ेढ़ परसैन्ट है । अगर इसी तरह से आबादी बढ़ती गई और उत्पादन नहीं बढ़ा तो जहां हम आज खड़े हुए हैं वहां पर खड़े रहेंगे बल्कि और पीछे हट जाएंगे । यह हमें ध्यान में रखना होगा कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के आधार पर हमें सारा काम करना होगा ।

यह जो 20 सूत्री कार्यक्रम है यह कोई बहुत नया कार्यक्रम नहीं है । इसमें वहीं चीजें हैं जो कांग्रेस बराबर, सदैव कहती आई है । कांग्रेस इन्हीं के आधार पर अपनी आई-ड्योलीजी, अपने विचारों का देश में प्रचार करती आई है । केवल सही नेतृत्व, हिम्मत, आत्म विश्वास और जन सहयोग पर आधारित है ।

इस वक्त यह देखा जाता है कि 7 लाख गांवों में भारत की 60-65 प्रतिशत जनता रहती है । मैं भी गांव का प्रतिनिधित्व करती हूं । मैं जानती हूं कि 6 बजे शाम को जब रात हो जाती है ज्यादातर गांवों में इतना भी नहीं है कि लोग वहां पर दीया जला सकें । वहां अन्धेरे में ही उनको रहना पड़ता है । जब कभी मैंने कानपुर बितहोर का दौरा किया है

वहां के कुछ गांवों में जहां 6 बजे अन्धेरा हो जाता है वहां लोगों को तेल जलाने तक के लिये नहीं मिलता है और अन्धेरे में ही अपनी रात गुजारनी पड़ती है । यह केवल बाहर का अन्धकार ही नहीं दिल में विवशता उत्पन्न करता है । हमारे देश के अन्दर गांवों में अन्दर जो हमारे भाई-बहिन काम करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, वे तभी देश की पैदावार बढ़ा सकते हैं जब हम उनकी मदद करें । जैसा अभी हमारे पंजाब के भाई ने कहा कि अगर पंजाब के गांवों के अन्दर लोगों को अच्छा बीज दिया जाय, पानी दिया जाय तो पंजाब पैदावार के मामले में सारे संसार में एक नमूना पेश कर सकता है । पंजाब ने अब तक इस प्रकार का नमूना दिखाया भी है । कई अन्य प्रदेशों में भी काफी काम हुआ है । अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा देश आज इतनी तरक्की कैसे करता । इस प्रकार के मौकों पर देश के सामने समस्याएं भी आती हैं । आप जानते हैं कि हमारा एनुअल प्लान 32 परसेन्ट बढ़ाया गया है और विशेषकर चाहे बिजली हो, माइनर एरीगेशन हो, कौल हो या स्टील का सवाल हो, इन सब की तरफ ध्यान दिया गया है । समस्याएं हमारे सामने आती हैं, लेकिन हमें एक लोकतंत्री तरीके से चलना है । बापू के दिखाये मंत्र—अहिंसा—के रास्ते से चलना है, सब को साथ लेकर चलना है । हम तानाशाही के रास्ते को ठीक नहीं मानते हैं । आज जरूरत इस बात की है कि हमारे रास्ते में जो रोड़े आते हैं, जो कठिनाइयां आती हैं उनको हमें दृढ़तापूर्वक हटाना है । हमारी प्रधान मंत्री जी के दृढ़ नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है । ससार में शायद ही कोई महिला तो क्या, कोई पुरुष होगा जिसका अपनी जनता पर इतना प्रभाव होगा जितना हमारी प्रधान मंत्री जी का है । क्या कारण है कि जब भी हमारी प्रधान मंत्री कहीं जाती हैं तो लाखों की भीड़ उनको सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती है ? दूर दर्शन हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं । हमारे देश में इस वक्त जो काम हो रहे हैं उनका फल आने वाले भविष्य में हमें अच्छी प्रकार से दिखाई देगा ।

इस एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के दौरान कई माननीय सदस्यों ने कई कमियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है । मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि कमियां तो रहेंगी । मैं समझती हूं कि जो आदमी काम करेगा तो उसके काम में कमियां रहेंगी । यह मानना बेवकूफी होगी कि हमारे काम में किसी तरह की कोई कमी नहीं है । जो आदमी काम नहीं करेगा तो उसके काम में कमियां कहां से आएंगी हम अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं और जो क्रिटिसिजम होगा उसको सुनकर हम उन कमियों को दूर करेंगे । हमारा रास्ता बहुत लम्बा है ।

We have miles to go.

हमारे रास्ते में जो रोड़े आएंगे, जो कठिनाइयां आएंगी, उनको हमें दूर करना है । हर चुनौती का हमें सामना करना है । हम अपने दिमाग के दरवाजे बन्द नहीं करना चाहते हैं । जिस जनता के बल पर अब तक हमने इतनी तरक्की की है उसी जनता के विश्वास पर हम आगे भी चलना चाहते हैं । इन शब्दों के साथ मैं उन तमाम सदस्यों को धन्यबाद देना चाहती हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया है ।

हमारे देश को विशेष कर तीन चीजों में विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था और ये तीन चीजें थी—फर्टिलाइजर, फूड और फ्यूयल लेकिन अब इन चीजों पर देश में ही ध्यान दिया जा रहा है और इसमें काफी सफलता मिली है । हमारे बैलेन्स आफ पेमेन्ट में काफी सुधार हुआ है । इंडस्ट्रीज के अन्दर हम काफी आगे बढ़े हैं । लाइसेंसिंग प्रोसीजर में काफी सुधार किया गया है । इन सब चीजों से आप देखेंगे कि देश के अन्दर एक बहुत बड़ा सोशियो-इकनोमिक ट्रांसफोरमेशन आफ सोसायटी हो रहा है । जनता स्वयं इस बात को समझ रही है । हमारे युवक नेता श्री संजय गांधी जी ने

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

अपना चार पाइन्ट का प्रोग्राम देश के सामने रखा है। अफोरेस्टेशन क्या है ? आप दिल्ली के अन्दर दिन में 2 बजे कहीं चले जाइये तो आपको केवल गर्मी का आभास होगा। लेकिन इस प्रकार से अगर हमारे देश में जंगलातों को काट दिया जाएगा तो डेजर्ट बढ़ते जाएंगे।

अभी हाल में एक वैज्ञानिक रिपोर्ट पढ़ी कि डिजर्ट एरिया बढ़ती चली जा रही है। उस पर रोक लगाने के लिए कम से कम यह अवश्य किया जाए कि नए पेड़ लगाए जाएं। इस प्रकार मान्यवर, अगर हर एक विद्यार्थी यह सोच ले कि हमें देश के हित में पेड़ लगाना चाहिए और ऐसा तो सम्भव नहीं कि पेड़ रात में लगे और सवेरे तैयार हो जाए, इस तरह का अहसास जब तक नहीं हो जाता, उसे यह महसूस नहीं होगा कि अपने भविष्य के निर्माण में, अपने देश को मजबूत बनाने में उसका क्या योगदान है। अगर एक पौधे को वह लगाता है, उस पौधे से प्रेम करता है, तो उस पौधे के निर्माण में वह भी देश का अभिन्न अंग बन जाता है। इसके पीछे एक बड़ी अच्छी फिलासफी है, इससे न केवल कृषि को फायदा होगा बल्कि भौगोलिक दृष्टि से भी फायदा होगा और देश के विकास की ओर एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। तो मैं इसका भी स्वागत करती हूं।

मान्यवर, जो पापुलेशन कट्रोल की बात है, संसार में हर सेकेण्ड में 3 बच्चे का जन्म होता है। हर बच्चा जो पैदा होता है उसके मां-बाप के मन में होता है : हमारा बच्चा राष्ट्रपति बने। तो उसको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, पढ़ायी की व्यवस्था चाहिए और आगे चल कर उसके लिए नौकरी चाहिए, सारे साधन चाहिएं। तो अगर इसी तरह संसार में पैदाइश होती रही तो हम किस प्रकार से उनको साधन दे सकेंगे ? सरकार की ओर से किसी प्रकार के कंपलशन का कोई सवाल उठा ही नहीं। हो सकता है कुछ लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाने में कुछ अधिक इन्थुजिआज्म दिखा दिया हो, हो सकता है उनकी मन्शा पूरी नहीं हो रही हो। यह समझने की बात है कि आज अगर हमारा प्रोडक्शन 5 प्रतिशत बढ़ता है और साथ में हम पापुलेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं और ढाई या 2 प्रतिशत के आधार पर बढ़ती चली जाती है तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं। तो हो सकता है कुछ लोगों ने इन्थुजिआज्म में आकर कुछ ज्यादा तेजी दिखायी हो। सरकार की ओर से कभी कंपलशन का सवाल नहीं उठा। मान्यवर, यह एक बेसिक प्रश्न है और एक मां के, बहिन के, औरत के रूप में अगर हमीं नहीं समझेंगे तो कैसे देश में प्रगति होगी, कैसे इस देश को आगे ले जाएंगे ? मैं आपके माध्यम से हर एक भाई से यहां कहूंगी कि जब कभी भी हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं, देश के किसी कोने में जाते हैं, गांव में या शहर में जाते हैं, ऐसे ब्लाक्स में जाते हैं जहां कोई साधन नहीं है, हमारा परम कर्त्तव्य है कि देश की सारी योजनाएं जो हम उनके लिए रख रहे हैं, उसके साथ यह भी देखें कि हमारी भावी पीढ़ी जो पैदा होगी वह पीढ़ी खाने से, पीने से और दूसरी सुख सुविधाओं से वंचित नहीं रहे। यह प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहती हूं।

मान्यवर, इसके साथ एक प्रश्न डावरी का है। यह सही बात है कुछ लोग आली शान तरीके से रहते हैं। हमारा काले धन का 1587 करोड़ रु० कहां से आ गया ? चोरी कर रखी होगी, कर नहीं दिया होगा, छुपा के रखा होगा। बहुत से काम पूजा के नाम पर गलत-सलत किए जाते हैं। मान्यवर, वह रुपया कैसे निकाला यह सब के समक्ष है। मुझे यह कहना है कि अगर सरकार ने सख्ती से, कड़ाई से और बड़ी

हिम्मत के साथ यह काम नहीं किया होता और जनता ने उसमें सहयोग नहीं दिया होता, तो यह बहुत कठिन काम था । विशेष रूप से हमारे जो कर्मचारी लगे हुए हैं इनकम टैक्स के, एक्साइज के, कस्टम के उन्होंने मिलकर तत्परता से काम न किया होता तो शायद इतना रुपया देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सामने नहीं आता । इसलिए जिन लोगों ने अभी तक एण्टी सोशल काम किया, चाहे बेकार का कंजम्शन करके किया, कांस्पिक्युअस कंजम्शन करके किया उसी से आज हमारे भाइयों के दिमाग में यह बात थी कि हमारे गरीब आदमियों और किसान के कंजम्शन के लिए कुछ नहीं रहा । आज गरीब आदमी को ऋण नहीं मिल रहा है । उसका कारण स्पष्ट है क्योंकि जिन्होंने काला धन कमाया आज वे ही अपने को बचाने के लिए, चोरी छिपाने के लिए चाहे इमारतें बना लेते चाहे विदेशों का चक्कर लगाते, चाहे कुछ और करते । आज उस रुपए की जहां पर खर्च करने की आवश्यकता है, जिस काम के लिए प्राथमिकता दी गई है, जहां पर हमारी आंकाक्षाओं के अनुसार और हमारी नीति के आधार पर उसको इस्तेमाल करना हमारा कर्त्तव्य है, वहां उसका उपयोग होना चाहिए । आज जो बुरी चीज है, जो दिखावटी चीज है, उसमें समाज में परिवर्तन लाने की आवश्यकता हैं, और परिवर्तन और क्रांति मान्यवर, जो आएगी वह कर्मों से बाद में आती है, विचार में पहले आती है । जब विचार पक्का होगा तो वे चीजें आसानी से ढह जाएंगी । इसलिए मेरा साथियों से निवेदन है, मैंने एक दफा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में पढ़ा था कि हमारा ग्रामीण क्रेडिट है उसमें ज्यादा से ज्यादा ऋण ऐसे होते थे जो कि बेचारा गांव वाला कुछ तो समाज की मर्यादा को निभाने के लिए करता है, जिससे चाहे तो कुंआ बना लेता, उसके लिए लिया था कुछ बैल के लिए ले लिया परन्तु जबान बच्ची है उसकी शादी करनी है, कैसे लोगों को नाक दिखाएंगे खर्च कर देता है, तो वह रुपया प्रोडक्टिव्ह न होकर अनप्रोडक्टिव्ह कामों में चला जाता है । इसलिए ऐसी चीजों को समाज के बीच से हटाकर एक बायकाट करने का वातावरण तैयार किया जाए तो उसमें हिम्मत आएगी । यह हिम्मत देने के लिए जो समाज के नेता हैं, और जो चुन कर आए हैं वे अगर कार्य करेंगे तो गरीबों के मन में भी आएगा कि बड़ा आदमी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए डाबरी के पीछे बड़ी भारी फिलासफी है जिसमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के माध्यम से बहुत कुछ काम हो सकता है ।

मान्यवर, इसमें अशिक्षा के बारे में तो कुछ कहना नहीं है क्योंकि अशिक्षा और अज्ञानता से बढ़कर और क्या हो सकता है ? जब दुःख सुख आता है तो उस वक्त चेतना कैसे आती है और मन में ढांढस कैसे आता है और आदमी किस चीज को पकड़कर रह सकता है ? हमारे जो बाप-दादा थे, दादा-दादी थी, उन्होंने बी० ए० , एम० ए० नहीं किया था , लेकिन जो सच्चाई है, जो आत्मीयता है, जो सच्ची विद्या है वह पहले हो और यह बहुत जरुरी चीज है और यह सब लोगों को मिलनी चाहिये । ज्वाइन्ट फैमिली में सब लोग, जो अपने से बड़े होते थे, उनसे सीख लेते थे । आज हमने जगह जगह स्कूल फैला दिये हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है, जो मौलिक चीज है, जिस चीज से आदमी आदमी बनना सीखता है, आदमी बनकर रहना सीखता है, दूसरों को टौलरेट करना सीखता है, इस तरह की शिक्षा हमें सब लोगों को देनी चाहिये । जाति के नाम पर नहीं, काम के नाम पर नहीं, रुपये के नाम पर नहीं बल्कि आज हमें इंसानियत के नाम पर आदमी को इंसान बनाने की जो शिक्षा है, वह देनी है और यह सारी चीज शिक्षा के लिए आवश्यक है ।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

मान्यवर, मेरा एक और अनुरोध है और वह यह है कि जहां यूथ कांग्रेस के माध्यम से, यूथ नेता के माध्यम से, आज हम चार बड़ी चीजें कर रहे हैं, वहां उसमें एक और चीज जोड़ दी जानी चाहिये। मेरे ख्याल में यह एक बहुत बड़ी चीज है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा मंतव्य है। अभी हमने आर्थिक समीक्षा देखी, हमने बजट देखा, टैक्स प्रपोजल्स देखें, हमने एप्रोप्रिएशन बिल देखा और ये सारी चीजें एक दिशा की ओर जा रही है और वह दिशा यह है कि हम अपनी आर्थिक ग्रोथ को किस तरह से एक्सलरेट करें। हमें अपने आर्थिक कार्यक्रम को शीघ्रता के साथ लेना चाहिये और हमारा जो आर्थिक कार्यक्रम है वह सामाजिक न्याय के आधार पर जा रहा है।

मान्यवर, इसके लिए रुपया चाहिये और जो हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम है उसके लिए भी हमें रुपये की आवश्यकता है। आज किसानों की भलाई के लिए हमने रूरल एरिया में हजारों राष्ट्रीयकृत बैंक खोल दिये हैं और कुछ ग्रामीण बैंक भी खुले हैं और खुल रहे हैं। आज हमें गांवों में कोआपरेटिव को मजबूत बनाना है जो केवल ऋण ही न दें बल्कि गांव के किसानों के हर तरह से सहायता भी करें। हमें गांवों में फार्मस सर्विस सोसाइटियां भी बनानी चाहिये। जैसा कि कई भाईयों ने कहा कि इसके लिए इंटिग्रेटेड क्रैडिट हो जिसके द्वारा किसानों को रुपया मिल सके, बीज प्राप्त हो सके, कच्चा माल प्राप्त हो सके और उन्हें सारी शिक्षा देकर माल भी तैयार करवा सकें। उनका जो माल तैयार होता है उसको मार्केटिंग करके उन्हें रुपया भी दिलवा सकें ताकि जो माल वे तैयार करें उससे उन्हें लाभ प्राप्त हो और इस तरह से वे अपने साधन बढ़ा सकें। इन सब चीजों के लिए रुपये की आवश्यकता होती है और रुपया टैक्स के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि अब एक नया तरीका आ रहा है जिसमें टैक्स लगाने के बजाय ज्यादा रुपया आता है और उसमें इंफैलेशन का भी ज्यादा असर नहीं होता है। हमारे लिए यह जो तरीका है वह बहुत ही सरल तरीका है और वह स्माल सैविंग का है। यह जो लघु बचत कहा जाता है, अल्प बचत कहा जाता है, मैं इसके सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि महाराष्ट्र में कई साल लघु बचत योजना और 9-10 साल लगातार अच्छी चली। उन्होंने देखा कि बगैर किसी प्रकार का टैक्स लगाये विकास कार्यों के लिए एक बहुत अच्छी खासी रकम प्राप्त हो जाती है। पिछले साल उत्तर प्रदेश ने भी इस तरह से करीब 90 करोड़ रुपया इकट्ठा किया अपने विकास कार्यों के लिए। हमारे पश्चिमी बंगाल ने भी यही कार्य किया और वह अपने देश में प्रथम आया। हमारे यहां जो योजना मंत्री बनकर श्री-शंकर घोष आये हैं, वे इसके इंचार्ज थे और उन्होंने ही इतनी बड़ी रकम इकट्ठा की। हमारे देश में जो छोटे छोटे साधन हैं उसके द्वारा हम रुपया जमा कर सकते है। हमारी जो इंवेस्टमैंट हैं वह पहले से सुधरी है और उस इंवेस्टमैंट क्लाइमेंट को और ज्यादा सुधारना है। हमें अपनी कैपिटल फारमेशन को बढ़ाना है। इसके लिए रुपये की आवश्यकता है। हमने कहा कि यह रुपया स्माल सेविंग्स के जरिये आ सकता है। देश का डोमेस्टिक सेविंग का रेट है वे हाल में घटे हैं, लेकिन अब वह चढ़ने शुरू हो गये हैं। मुझे यह कहते खुशी होती है कि जो लघु बचत योजना है उसमें पिछले साल मंहगाई के कारण लोगों ने कम रकम लगाई। लोगों के ऊपर मंहगाई की वजह से जो कष्ट आ गया था उसकी वजह से उन्होंने पोस्ट आफिस से रुपया निकाल लिया था, लेकिन इस साल उसमें अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। हमें पूरा

विश्वास है कि स्माल सैविंग्स का जो हमने लक्ष्य रखा है वह पूरा होकर रहेगा और एक्सीड कर जायेगा। इसलिए मेरा अपने साथियों से एक मौलिक अनुरोध है कि आज हमारे देश में दस करोड़ विद्यार्थी हैं। *(Interruptions)* I want to take you into confidence. It is through you that I would like to operate because that is the way to operate. मान्यवर, आज हमारे देश में 10 करोड़ विद्यार्थी हैं, चाहे वे नर्सरी स्कूल के बच्चे हों चाहे यूनिवर्सिटी के लड़के हों। आज इस संचयिका के काम में बहुत से लोग लगे हुए हैं। अगर हर मां बाप देखे कि हरेक बच्चा एक रुपया वालन्टरी रूप से जमा करे तो बहुत बड़ी रकम इकट्ठा हो सकती है। इसके पीछे कोई कम्पलशन नहीं है, केवल अनुरोध है क्योंकि देश के हित में यह चीज है। अगर हर मां बाप हर बच्चा प्रति माह एक रुपया जमा करे ——देश में 40 प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जो हर माह नहीं बचा सकते लेकिन ऐसे भी होंगे जो 5 रुपये महीने भी बचा सकते हैं——तो 100 करोड़ रुपये हर साल औसत वालंटरी रूप से इकट्ठा हो सकते हैं। मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगी कि जो चार-सूत्री कार्यक्रम युवकों ने लिया है उसमें छोटी बचत को भी शामिल कर लें। इससे हमारी डोमेस्टिक सैविंग्स बढ़ेंगी जिसका कि नानइन्फेलशनरी करेक्टर होगा।

मैं अपने साथियों को धन्यवाद देती हूं। आज जो चुनौती देश में आई है उसके बारे में किसी साथी ने कल कहा था कि 'स्काई इज क्लियर'। मान्यवर, स्काइ इज क्लियर टु डे। आज देश में एक नई फिजा है। उस फिजा में चुनौती के साथ, हिम्मत के साथ, शालीनता के साथ, आत्मीयता के साथ, सिन्सेरिटी के साथ कांग्रेस का जो प्रोग्राम है, जो बापू ने अहिंसा के माध्यम से हमको दिया था, उसे पंडित जी की दूर-दृष्टि को अपनाते हुए इंदिरा जी के नेतृत्व में युवकों का सहयोग लेकर हर महिला, बुजुर्ग और बच्चे को मिलकर देश के विकास में पंचवर्षीय योजना का जो हमारा सबसे बड़ा यज्ञ चल रहा है उसमें अपना छोटा योगदान करना है। इन शब्दों के साथ मैं आपको और सदन को धन्यवाद देती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : The suggestion is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1976-77, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration".

The motion was adopted-

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 *and the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Sir, I move :

"That the Bill be returned."

The question was proposed.

DR. RAMKRIPAL SINHA (Bihar) i Sir, I want to put forward a suggestion to the Government at this stage, and that is that our financial year should start at another time. In several States like Bihar, Orissa and some other eastern States and some of the Southern States also the rains start in the month of June, When the grants are made to different Ministries, they are not in a position to execute their schemes. They get only one or two months, April and May to work. They have to sit idle for four months during the rainy season and then again they have to sit idle. So it is high time the Government took note of this and changed our financial year. My suggestion is that our financial year should start after October or November so thai we get more time, particularly, for constructive programmes like roads, bridges, buildings, to work for at least 6 or 7 months

[Dr. Ramkripal Sinha] and the working period from March and April which is spent in office work accounting and budgeting, this and that, all these things, should be finished in the rainy season. So I would request the Government to think very deeply in the matter and change our financial year starting it from October or November instead of starting from the month of April.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : This is a suggestion to the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl LOKANATH MISRA) : The question is : "That the Bill be returned." *The motion was adopted.* THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 19th May, 1976.